



औरंगजेब को आदर्श मानने वाले विधायक को उत्तर प्रदेश भेजिए, इलाज कर देंगे'

अबू आजमी का नाम लिए बिना योगी का हमला

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर हमले किए और कहा कि हमारे के लिए महाकुंभ गर्व का विषय है जबकि सपा के लोग औरंगजेब को नायक मानते हैं। महाकुंभ के आयोजन को पूरी दुनिया याद रखेगी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बजट सत्र में विधान परिषद को संबोधित करते हुए महाकुंभ के आयोजन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा आयोजन था जिसे लंबे समय तक दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां इससे सहमत नहीं थीं और महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डिगी।

उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन की दुनिया भर में प्रशंसा



हो रही है। जो लोग संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं वो भी महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। 45 दिन तक चले आयोजन में कोई लूट की घटना नहीं हुई। कोई अपहरण की घटना नहीं हुई। यह सनातन के सामाजिक अनुशासन का प्रभाव है। जो कि कहता है कि पूरा देश एक है और यहां जातिवाद और

क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये उन लोगों को जवाब है जो कि जल के प्रदूषण और अन्य तमाम छोटी खबरों को लेकर आयोजन पर सवाल उठा रहे थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। देश की जनता के लिए गंगा सबसे पवित्र है और विज्ञान कहता है कि बहता हुआ जल खुद को पवित्र

करता रहता है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ में जैसी जिसकी दृष्टि थी वैसा ही उसने वहां देखा। सनातन के मानने वालों के लिए महाकुंभ एक गर्व का विषय है जो कि पूरी दुनिया को एकता का संदेश देता है।

महाकुंभ के आयोजन के दौरान काशी और अयोध्या में भी पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई। इस दौरान इन नगरों के स्थानीय लोगों ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया साथ ही उनका आतिथ्य सत्कार भी किया।

एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपये की कमाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था को आजीविका से जोड़ा है। यही कारण है कि प्रयागराज का एक नाविक परिवार जिसके पास 130 नावें थीं।

शेष पेज 2 पर

मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी

11 सेकंड का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस

बस्ती । अभिषेक कुमार दुबे की तहरीर पर बस्ती में केस दर्ज किया गया है। वीडियो में दिख रहा है किसी के पृष्ठ पर आरोपी बोल रहा है सीएम योगी तो बम से उड़ाऊंगा। वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से

उड़ाने की धमकी का एक वीडियो वायरल हुआ है। 11 सेकंड के वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभिषेक कुमार दुबे ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वह

सनातन धर्म सर्वोपरि नामक वाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं। इस ग्रुप में 533 सदस्य हैं। उसी ग्रुप के एक सदस्य, जो ग्रुप एडमिन भी है, ने एक वीडियो डाला, जिसमें एक व्यक्ति मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कह रहा है कि योगी को बम से उड़ा दूंगा।

भाषा विवाद के बीच कमल हासन का केंद्र पर निशाना

नई दिल्ली। पार्टियों ने सामूहिक रूप से पीएम मोदी को एक संयुक्त प्रस्ताव सौंपा, जिसमें आवासन दिया गया कि कोई भी परिसीमन अभ्यास, यदि अब आयोजित किया जाता है, तो 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होगा और अगले 30 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। अभिनेता-राजनेता कमल हासन ने बुधवार को चल रहे भाषा विवाद में एमके स्टालिन के रुख का समर्थन किया और केंद्र पर गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपकर भारत को "हिंदिया" बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उनकी टिप्पणी तमिल पार्टियों की एक बैठक में भाग लेने के दौरान आई जहां हिंदी थोपने और परिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनाया गया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। अभिनेता सीएम स्टालिन के नेतृत्व में 50 से अधिक तमिल राजनीतिक दलों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

शेष पेज 2 पर

केंद्र सरकार ने HLDC के तहत सस्ती जेनरिक पशु दवाओं की आपूर्ति को दी मंजूरी, नए प्रावधान जोड़े

नई दिल्ली। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम और इलाज के लिए संचालित केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का तहत पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पशुपालन को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3,880 करोड़ रुपये के पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी देकर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनरिक पशु चिकित्सा दवाओं के वितरण को मंजूरी दे दी है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) पशुओं में होने वाले रोगों की रोकथाम और इलाज के



लिए संचालित केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना का तहत पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और पशुपालन को बढ़ावा देना है। एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल बजट 3,880 करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई।

शेष पेज 2 पर

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे प्रोजेक्ट्स को मोदी सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। केदारनाथ रोपवे परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 4,081.28 करोड़ रुपये होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की संयुक्त लागत के साथ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि 12.9 किलोमीटर लंबी केदारनाथ रोपवे परियोजना की लागत



4,081 करोड़ रुपये से अधिक होगी, जबकि 12.4 किलोमीटर लंबी हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की लागत 2,730 करोड़ रुपये होगी। दोनों परियोजनाएं पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा होंगी।

केदारनाथ रोपवे परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम-पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। परियोजना की

कुल लागत 4,081.28 करोड़ रुपये होगी। परियोजनाओं से यात्रा काफी कम होकर 36 मिनट रह जाएगी। अभी केदारनाथ पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। परियोजना का विवरण देते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रत्येक गंडोला की क्षमता 36 लोगों की होगी। यह प्रोजेक्ट ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विशेषज्ञों की मदद से पूरा किया जाएगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, केदारनाथ मंदिर की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की

चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल या टट्ट, पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा कवर किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यह मंदिर साल में अक्षय तृतीया (अप्रैल-मई) से दिवाली (अक्टूबर-नवंबर) तक लगभग 6 से 7 महीने तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है, और सीजन के दौरान सालाना लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहां आते हैं।

पटना। तेजस्वी ने पिछले साल जनवरी में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। बार-बार पाला बदलने के कारण 'पलटू राम' का टैग हासिल करने वाले नीतीश ने 2022 में विपक्ष के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के लिए एनडीए छोड़ दिया था।

बिहार विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक के एक दिन बाद राजद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजद नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि अक्षम सरकार को पैकिंग के लिए भेज दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने



लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। भूल जाइए कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उनसे पहले भी मेरे पिता दो बार विधायक और एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव को भूल जाइए, लालू जी ने कई प्रधानमंत्री बनाए हैं। यह मैं ही था जिसने उन्हें (नीतीश कुमार) दो बार सीएम बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। राज्य में सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ एक थका हुआ मुख्यमंत्री है।

शेष पेज 2 पर

अमेरिका-यूक्रेन के बीच खनिज समझौते पर होंगे हस्ताक्षर?

डोनाल्ड ट्रंप बोले- उन्हें जेलेंस्की से एक पत्र मिला है

नई दिल्ली। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का प्राप्त एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि युद्ध प्रभावित देश के राष्ट्रपति पुनः वार्ता की मेज पर आना चाहते हैं।

अपने घंटों लंबे भाषण के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से एक पत्र मिला है, जिसके कुछ ही दिनों बाद सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की गई थी और यूक्रेन को अमेरिकी सहायता निलंबित कर दी गई थी। जेलेंस्की ने अपने पत्र में एक खनिज सौदे पर बातचीत



करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का प्राप्त एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि युद्ध प्रभावित देश के राष्ट्रपति पुनः वार्ता की मेज पर आना चाहते हैं।

दरअसल, पिछले हफ्ते

ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की ट्रंप के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए वार्ता को विफल माना जा रहा था। ट्रंप ने कहा, हमने रूस के साथ गंभीर चर्चा की है और हमें इस बात के मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं।

शेष पेज 2 पर

टैरिफ

क्या है जवाबी आयात शुल्क: ट्रंप ने अप्रैल से भारत पर लगाने

ट्रंप ने अप्रैल से भारत पर लगाने की धमकी क्यों दी, इससे कितना होगा नुकसान?

ट्रंप की धमकी या व्यापार जंग का एलान?



नई दिल्ली। यह जवाबी टैरिफ क्या हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाने की धमकी दी है? भारत के खिलाफ लगाए गए इन टैरिफ की गणना कैसे होगी? भारत को अपना सहयोगी बनाने वाले ट्रंप यह कदम उठा क्यों रहे हैं? इसके अलावा भारत पर इस कदम का क्या असर होगा? आइये जानते हैं...

भारत हमसे 100% ऑटो टैरिफ वसूलता है, चीन हमसे दोगुना टैरिफ

वसूलता है, दक्षिण कोरिया चार गुना टैरिफ लगाता है। यह दोस्त और दुश्मन दोनों की तरफ से हो रहा है। यह प्रणाली अमेरिका के लिए उचित नहीं है, यह कभी नहीं थी।" अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में अपने पहले संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे तौर पर न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि 2 अप्रैल से हमारे उत्पादों पर जवाबी आयात

भारत पर ट्रंप के फैसले का क्या असर होगा?

अमेरिकी उत्पादों की कीमतों पर-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिसप्रोकल टैरिफ के फैसले को लेकर भारत में पहले से ही चिंताएं हैं। - इसके चलते भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पादों-मोटरवाइक, शराब व कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का फैसला किया है। - ट्रंप के संसद में किए गए एलान के मद्देनजर व्यापार युद्ध से बचने के लिए भारत अभी कुछ और अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटा सकता है। - इतना ही नहीं भारत ने व्यापार में आ रहे अंतर को कम करने के लिए अमेरिका से रक्षा उत्पादों, तेल और गैस को ज्यादा खरीदने की बात कही है, ताकि दोनों देशों के आयात-निर्यात के अंतर को कम किया जा सके। रुपये की कीमत पर-आने वाले समय में इसका असर यह होगा कि आयात शुल्क घटने के बाद भारत में अमेरिकी उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी। हालांकि, इससे रुपया कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मांग कम हो जाएगी। इसी तरह मांग बढ़ने की वजह से डॉलर और मजबूत होता जाएगा। (यहां पढ़ें व्यापार का मुद्दा पर असर) शेष पेज 2 पर शुल्क यानी रिसप्रोकल टैरिफ यानी अन्य देशों ने दशकों से हमारे 'जैसे को तैसा टैरिफ' लगाने का खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया एलान भी कर दिया। ट्रंप ने कहा, है। शेष पेज 2 पर

असम के तिनसुकिया जिला आयुक्त स्वप्निल पाल को द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट पुरस्कार से सम्मानित

बेजुबान भी हैं अनमोल... हर साल हजारों पशु-पक्षियों की जान बचा रहा दिल्ली का दमकल विभाग

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
असम : असम के तिनसुकिया जिला आयुक्त स्वप्निल पाल को देश की प्रमुख अखबार संस्थान इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशासक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक वर्ष के भीतर तिनसुकिया (तिंगराई), दमदुमा और मार्घेरिटा में डंपसाइट्स से 1.53 लाख मीट्रिक टन कचरे को पूरी तरह से खत्म करने में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिला है। पहली बार, एक जिले ने कचरे की इस मात्रा के निपटान के लिए जैव-खनन और



बायोरेमेडिएशन विधियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसने वास्तव में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा

खोली है। कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

उन्हें औपचारिक रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इंडियन एक्सप्रेस समूह की एक विज्ञापित में, यह कहा गया है कि उन जिला मजिस्ट्रेटों को पुरस्कार दिए गए हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें तिनसुकिया के जिला आयुक्त स्वप्निल पाल भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, पाल को पिछले साल असम सरकार द्वारा दिए गए कर्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

नई दिल्ली । वर्ष 2024 में दमकल कर्मियों ने 3467 पशु और 2789 पक्षियों की जान बचाई। वहीं, वर्ष 2023 में 3510 पशु और 3809 पक्षियों की जान बचाई गई। इस साल यानी वर्ष 2025 के शुरुआती दो माह की बात करें तो जनवरी और फरवरी 490 पशु और 351 पक्षियों की जान बचाई गई।

पतंग की डोर में उलझे कबूतर से लेकर गड्डे में गिरी गाय को बचाने तक दिल्ली का दमकल विभाग हर साल हजारों बेजुबानों की जान बचाता है। कई बार कई-कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद दमकलकर्म अपनी जान पर खेलकर इनको बचाते हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक इंसानी जान की तरह परिंदों और जानवरों की जान भी उनके लिए महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों का कहना है कि जानवरों और पक्षियों के लिए हम मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। दैनिक जीवन में पशु-पक्षी इसका शिकार भी हो रहे हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस के आसपास उड़ने वाली पतंग की



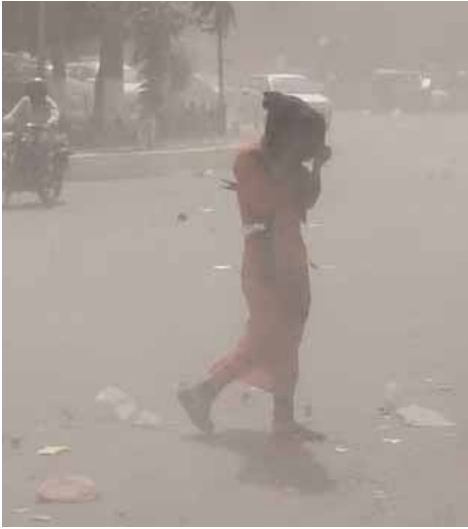
डोर में हजारों पक्षियों की जान चली जाती है। सबसे ज्यादा पक्षियों को बचाने की कॉल जुलाई, अगस्त और सितंबर में आती है।

अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2024 में दमकल कर्मियों ने 3467 पशु और 2789 पक्षियों की जान बचाई। वहीं, वर्ष 2023 में 3510 पशु और 3809 पक्षियों की जान बचाई गई। इस साल यानी वर्ष 2025 के शुरुआती दो माह की बात करें तो जनवरी और फरवरी 490 पशु और 351 पक्षियों की जान बचाई गई। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि इंसानी जान के अलावा विभाग के लिए हर बेजुबान जानवर और पक्षियों की जान भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार तो दमकलकर्म अपनी जान पर खेलकर इन बेजुबानों की जान बचाते हैं। कई बार जानवर

दमकल कर्मियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। अक्सर गाय या दूसरे जानवरों के नाले या किसी गहरे गड्ढे में गिरे की कॉल आती है। इसके अलावा पेड़ों और तारों पर लटके मांझे में पक्षी उलझकर फंस जाते हैं। कई बार किसी ऊंची इमारत पर बिल्ली, बंदर या कोई दूसरा पशु-पक्षी फंसाता है तो उसको भी बचाने के लिए पूरी जान लगा दी जाती है। गर्ग ने बताया कि पशु और पक्षियों को बचाने के लिए वह आधुनिक से आधुनिक मशानों का इस्तेमाल करते हैं। बेजुबानों को बचाने के बाद आम लोगों से विभाग को खूब तारीफ मिलती है, इससे जवानों का हौसला बढ़ता है। कॉल मिलने के बाद उनकी टीम की प्राथमिकता समय पर पहुंचकर बेजुबान की जान बचाना है।

ठंडी हवाओं से तापमान लुढ़का, सर्दी का हुआ अहसास क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 25 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 11.8 डिग्री दर्ज हुआ। दो दिनों से चल रही ठंडी हवाओं ने चढ़ते पारे से लोगों को निजात दिला दी है। बुधवार को तापमान लुढ़कने से सर्दी का अहसास हुआ। ऐसे में फिर से लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए। हालांकि, एक सप्ताह तक दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 9 व 10 मार्च तक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4



डिग्री कम 25 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 11.8 डिग्री दर्ज हुआ। 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 फरवरी को तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

इसी तरह न्यूनतम तापमान 27 फरवरी को 19.5 दर्ज किया गया, जो पिछले 74 वर्षों में सबसे अधिक था, लेकिन 3 मार्च को यह लुढ़ककर 9.6 डिग्री तक पहुंच गया। अब चार मार्च से तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बृहस्पतिवार को भी तेज सतही हवाएं चलने के आसार हैं, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।

पेज एक का शेष...

औरंगजेब को आदर्श मानने वाले विधायक को उत्तर प्रदेश भेजिए, इलाज कर देंगे

उन्होंने पूरे आयोजन के दौरान 30 करोड़ रुपये की कमाई की। महाकुंभ का वृहद आर्थिक पक्ष है। हमारा अनुमान है कि इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन लाख करोड़ का लाभ हुआ है। औरंगजेब सपा के लोगों का नायक मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा को उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा को उस नेता के बयान का खंडन करना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। नहीं तो उसे यहां बुलाइये। हम उसका इलाज कर देंगे। यूपी ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। ये लोग महाकुंभ को कोसते हैं और औरंगजेब पर गर्व करते हैं। उसे यूपी भेज दीजिए हम इलाज कर देंगे। बता दें कि अबू आजमी ने बयान दिया था कि वह औरंगजेब पर गर्व करते हैं।

हमने नीतीश को दो बार सीएम बनाया, मुख्यमंत्री पर तेजस्वी का पलटवार, विधानसभा में हुई थी नोकझोंक

मंगलवार को मुख्यमंत्री ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि बिहार में पहले क्या था? वह मैं ही था जिसने आपके (तेजस्वी यादव) पिता को बनाया। यहां तक ? ?कि आपकी जाति के लोग भी मुझसे पृष्ठ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी उनका समर्थन किया। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब तेजस्वी ने पिछले साल जनवरी में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। बार-बार पाला बदलने के कारण पलटू राम का टैग हासिल करने वाले नीतीश ने 2022 में विपक्ष के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के लिए एनडीए छोड़ दिया था। हालाँकि, उन्होंने यू-टर्न ले लिया और 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में लौट आए। चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं, राजद और तेजस्वी नीतीश के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं।

केंद्र सरकार ने लूटलूट के तहत सस्ती जेनरिक पशु

दवाओं की आपूर्ति को दी मंजूरी, नए प्रावधान जोड़े

एलएचडीसीपी योजना में अब पशु औषधि का एक नया हिस्सा जोड़ा गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, मंत्रिमंडल में पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लिया गया है। इस योजना के पशु औषधि घटक के तहत उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों पर मिलेंगी। वैष्णव ने कहा कि यह पशु औषधि, जन औषधि योजना के समान होगी। अब जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं पीएम किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित की जाएंगी। पशु चिकित्सा दवाओं के पारंपरिक ज्ञान को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और योजना के हिस्से के रूप में इस पारंपरिक ज्ञान का भी दस्तावेज तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पशु औषधि के प्रावधान के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की आपूर्ति और बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए कुल बजट आवंटन से 75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

भाषा विवाद के बीच कमल हासन का केंद्र पर निशाना

पार्टियों ने सामूहिक रूप से पीएम मोदी को एक संयुक्त प्रस्ताव सौंपा, जिसमें आश्वासन दिया गया कि कोई भी परिसीमन अभ्यास, यदि अब आयोजित किया जाता है, तो 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होगा और अगले 30 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। उन्होंने तर्क दिया कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हासन ने कहा कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि सभी राज्य हिंदी बोलें और बहुमत से चुनाव जीतें। हमारा सपना है 'इंडिया' और उनका है 'हिन्दिया'। हासन की टिप्पणी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 'हिंदिया' तंज की तर्ज पर थी, जब अमित शाह ने हिंदी दिवस पर कहा था कि यह "एक भाषा है जो दुनिया में भारत की पहचान को चिह्नित करती है"। स्टालिन ने टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा था, "यह भारत है, हिंदिया नहीं"। पिछले हफ्ते, हासन ने केंद्र को चेतावनी दी थी, हूतमिलवासियों ने एक भाषा के लिए अपनी जान गंवाई है। इसके साथ मत खेले।

ट्रंप ने अप्रैल से भारत पर

लगाने की धमकी क्यों दी, इससे कितना होगा नुकसान?

अब उन अन्य देशों के खिलाफ उनके हथियार का ही इस्तेमाल करने की हमारी बारी है। औसतन यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं। उनकी तुलना में हम उनसे कम टैरिफ लेते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। विचौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद आया है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर यह जवाबी टैरिफ क्या हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाने की धमकी दी है? भारत के खिलाफ लगाए गए इन टैरिफ की गणना कैसे होगी? भारत को अपना सहयोगी बताने वाले ट्रंप यह कदम उठा क्यों रहे हैं? इसके अलावा भारत पर इस कदम का क्या असर होगा? आइये जानते हैं... पहले जानें- क्या होते हैं टैरिफ ? रिसप्रोकल टैरिफ यानी परस्पर और जवाबी टैरिफ को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर टैरिफ, जिन्हें आयात शुल्क भी कहा जाता है, वह क्या होते हैं? आसान भाषा में समझें तो टैरिफ वह शुल्क होता है, जो कोई देश किसी अन्य देश से आयात होने वाले सामान पर लगाता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई अमेरिकी नागरिक भारत में उत्पादकों से नागपुरी संतरे मंगाता है, तो उसे न सिर्फ उन संतरों का भुगतान करना होगा, बल्कि उसे एक अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। यह शुल्क उस देश की सरकार लगाती है, जहां यह उत्पाद आयात किया जा रहा है। इसे ही आयात शुल्क कहा जाता है। अलग-अलग देशों की सरकारें अपने यहां आयात होने वाले सामानों पर अलग-अलग शुल्क लगाती हैं और अपने खजाने को भरती हैं। कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, न कि कुआं प्यास बुझाने के लिए प्यासे के पास। यह कहावत दो देशों के बीच व्यापार में भी लागू होती है। मसलन अगर अमेरिकी नागरिकों को भारत के उत्पाद की जरूरत है तो वह इन चीजों का आयात भारत से करेंगे। इतना ही नहीं वे इन उत्पादों पर अपनी सरकार की तरफ से लगाए गए आयात शुल्क को भी चुकाएंगे, ताकि उत्पाद उनके पास पहुंच सके। यह मांग और आपूर्ति का नियम है। एक-दूसरे पर अलग-अलग दर से टैरिफ क्यों लगाते हैं देश ? दूसरे युद्ध के बाद से ही कई देशों ने अपने उत्पादों के आयात-निर्यात पर शुल्क न लगाने का फैसला किया था और उत्पादों पर टैरिफ न लगाकर व्यापार को अधिकतर मुफ्त रखा। यानी अगर कोई दो देश एक-दूसरे पर आयात शुल्क नहीं लगाते तो उनके नागरिकों को कोई उत्पाद एक-जैसी कीमत पर ही मिलेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा

उत्पाद को पहुंचाने का शुल्क (डिलीवरी फीस) ही जुड़ सकती है। हालांकि, यह नियम अधिकतर विकसित देशों पर लागू होते हैं, क्योंकि इन देशों के पास पहले से ही मजबूत अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षमताएं मौजूद रहीं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि चूंकि विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ रही है और इनमें उद्योगों को भी विकसित करने की जरूरत है, इसलिए इन्हें आयात शुल्क लगाने की छूट दी जा सकती है।

भारत और अमेरिका के मामले में भी यही नियम लागू होता है। जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था 19वीं सदी में ही मजबूत हो चुकी थी, वहीं भारत की आर्थिक स्थिति 20वीं सदी के अंत में बेहतर होना शुरू हुई। इसलिए विकसित देश- अमेरिका के मुकाबले विकासशील देश- भारत को ज्यादा आयात शुल्क वसूलने की छूट दी जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि इन शुल्कों के जरिए भारत और अन्य विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं और अपना विदेशी मुद्रा भंडार भी भर सकते हैं।

अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर भारत से कार मंगाता है तो 10 लाख कीमत वाली कार के लिए उसे आयात शुल्क के साथ करीब 12 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत का कोई शख्स अमेरिकी कार खरीदता है तो उसे ज्यादा आयात शुल्क की वजह से 20 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे। यह कीमतें इन उत्पादों को पहुंचाने की कीमत (डिलीवरी फीस) को जोड़े बिना है। अब तक इस तरह की व्यवस्था को डब्ल्यूटीओ ने मान्यता दी है। यह व्यवस्था काफी हद तक सही भी रही है। इसे कृषि क्षेत्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका में बड़े स्तर पर कृषि उत्पाद पैदा होते हैं। वहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों- गेहूं, धान, आदि पर भारत उच्च दरों पर आयात शुल्क लगाना बंद कर दे तो यह उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में भारत के किसानों के उत्पादों की भारत में ही खरीद कम होने की आशंका रहेगी। इससे भारतीय किसानों का घाटा काफी ज्यादा हो सकता है।

वहीं, अगर अमेरिका भारत से आने वाले कृषि उत्पादों पर निम्न स्तर के आयात शुल्कों को बढ़ा दे तो अमेरिका में भारतीय किसानों की उपज की कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में वहां भारतीय उत्पादों की मांग घटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे भारतीय किसानों को घाटा उठाना होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पूरी व्यवस्था आयात शुल्क या टैरिफ कहलाती है। अलग-अलग देश एक-दूसरे पर अलग टैरिफ लगाते हैं, जिससे व्यापार का संतुलन बना रहता है।

ट्रंप आखिर बराबरी के टैरिफ लगा क्यों रहे हैं ?

चौंकाने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का प्रचार करना है। ट्रंप खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि दुनिया के कई देश ज्यादा आयात शुल्क वसूलते हैं, जिससे अमेरिका को घाटा होता है। इसलिए अमेरिकी सरकार उन देशों से ज्यादा टैरिफ वसूलेगा, जिससे अमेरिकी खजाने में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका- उत्पादों पर टैरिफ का शुल्क उस देश के नागरिकों-व्यापारियों को ही चुकाना पड़ता है, जहां की सरकार ने आयात शुल्क लागू किया है।

इतना ही नहीं एक व्यापारी होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) के खिलाफ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच कारों के आयात-निर्यात का उदाहरण ले लें तो

भारत से 10 लाख रुपये की एक कार को आयात करने के लिए अमेरिकी नागरिक को 12.5 लाख चुकाने पड़ते हैं। वहीं, अमेरिका में बनी इसी कीमत की कार को भारत में खरीदने के लिए 20 लाख देने पड़ते हैं।

यानी भारत को ज्यादा आयात शुल्क की वजह से अमेरिका से आई कार पर 7.5 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। भारत का यही लाभ अमेरिका के लिए व्यापार घाटा कहा जाता है।

इसी तरह अलग-अलग देशों से बिजनेस में अमेरिका का कुल व्यापार घाटा 1 लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ आयात शुल्क की वजह से चीन का व्यापार में फायदा (ट्रेड सरप्लस) 1 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी अंतर को खत्म करने की बात कही है।

तो क्या व्यापार घाटा बुरी चीज है ? दो देशों के बीच जब व्यापार होता है, तो किसी एक देश का व्यापार हमेशा दूसरे से ज्यादा होगा। इसकी वजह ज्यादा आयात या निर्यात हो सकता है।

सीधे शब्दों में अमेरिका ने भारत से ज्यादा उत्पादों और सेवाओं की खरीद की, जबकि भारत ने अमेरिका से कम उत्पाद-सेवाएं खरीदीं। इसके चलते अमेरिकी नागरिकों की मुद्रा ज्यादा खर्च हुई। वहीं भारतीय नागरिकों की मुद्रा का खर्च कम रहा।

भारत पर ट्रंप के फैसले का क्या असर होगा ?

भारत की जीडीपी-अर्थव्यवस्था पर-भारत में हाल ही में पेश हुए बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं और अब 12 लाख रुपये से कम कमाने वालों पर नई कर व्यवस्था के तहत आयकर नहीं लगेगा। केंद्र का यह फैसला मुख्यतः इसलिए आया था, ताकि भारतीयों के हाथ में पैसा बढ़ जाए और वह इस बचे

हुए धन का इस्तेमाल घरेलू खर्चों में बढ़ा सकें। इससे भारत का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) तेजी से बढ़ती।

हालांकि, अगर अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटता है तो भारतीय आयकर के दायरे से बची हुई रकम को सस्ते होने वाले अमेरिकी उत्पादों पर खर्च कर सकते हैं।

इससे भारतीयों का धन अमेरिकी व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगा और अमेरिकी जीडीपी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी।

वहीं, घरेलू उत्पादों की मांग कम होने से देश की जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

इसका असर आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कम दर पर उपलब्ध होने की वजह से उपभोक्ता अमेरिकी उत्पादों में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं।

अमेरिका-यूक्रेन के बीच खनिज समझौते पर होंगे हस्ताक्षर ?

पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक विवादस्पद बैठक के बाद इस सौदे को रोक दिया गया था, जिसमें जेलेंस्की को अचानक छोड़ दिया गया था।

उस बैठक के दौरान, ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए सुझाव दिया कि उन्हें मीडिया के सामने अतिरिक्त सहायता मांगने के बजाय अमेरिकी समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। ट्रंप ने कहा था, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा, मैं भी यूक्रेन में क्रूर संघर्ष को खत्म करने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर हफ्ते हजारों रूसी और यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं और उन्होंने संघर्ष को रोकने की इच्छा व्यक्त की, उन्होंने अलंकारिक रूप से पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि यह अगले पांच वर्षों तक चलता रहे ?"

उन्होंने यूक्रेन को सहायता देने की तुलना में रूसी तेल पर अधिक खर्च करने के लिए यूरोप की आलोचना की और इसकी तुलना यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सैकड़ों अरबों डॉलर की सहायता से की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन पर 300 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं जबकि यूरोप ने 100 अरब डॉलर खर्च किए हैं। पिछले हफ्ते की बैठक के नतीजों के बावजूद, अमेरिकी अधिकारी कीव में अपने समकक्षों के साथ संपर्क में हैं, उन्हें खनिज सौदे पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जेलेंस्की के सलाहकारों को यूक्रेनी राष्ट्रपति को ट्रम्प से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मनाने की सलाह दे रहे हैं, जैसा कि रॉयटर्स ने स्थिति से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ

सुरेंद्र मलानिया

बड़ौत/बागपत- दिगंबर जैन कॉलेज, बड़ौत के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (उत्तर) के सप्त दिवसीय विशेष शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। यह शिविर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बाड़ोली रोड पर आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

शिविर का शुभारंभ एवं प्रमुख गतिविधियाँ

शिविर का आरंभ ईश वंदना एवं लक्ष्य गीत से हुआ, जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. महेश कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को सेवा कार्यों के प्रति प्रेरित किया और समाज में उनके योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र इकाई द्वितीय की छात्राओं ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने वहाँ पौधों की निराई-गुड़ाई एवं सिंचाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही, छात्राओं ने आजाद नगर मलिन बस्ती का दौरा



किया, जहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों को डेंगू, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने स्वच्छता और आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया।

खेलकूद एवं आपसी सौहार्द का प्रदर्शन

शिविर के दौरान छात्राओं के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिसमें सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन खेलों के माध्यम से छात्राओं ने टीम वर्क और खेल भावना का परिचय दिया। इसके अलावा, छात्राओं ने एक-दूसरे के साथ अल्पाहार साझा किया, जिससे

आपसी प्रेम और सहयोग की भावना प्रकट हुई।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ.

रुचिका जैन का प्रेरणादायक संदेश

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रुचिका जैन ने छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने 'मैं नहीं, तुम नहीं, हम' के सिद्धांत को समझाते हुए बताया कि समाज सेवा में निःस्वार्थ भावना और एकता का होना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित किया कि वे समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाएँ।

महिला सशक्तिकरण रैली बनी

मुख्य आकर्षण

शिविर के पहले दिन का मुख्य आकर्षण इमहिला सशक्तिकरण पर आधारित विशाल रैली रही। यह रैली दिगंबर जैन कॉलेज से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बाड़ोली रोड पर संपन्न हुई। छात्राओं ने इस दौरान नारेबाजी और पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से समाज को महिला अधिकारों, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का संदेश दिया।

शिविर में 50 से अधिक छात्राओं की भागीदारी

शिविर में लगभग 50 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्राओं ने सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। इस सफल आयोजन ने राष्ट्रीय सेवा योजना के रसेवा, शिक्षा और सर्म्पर्णर के मूल्यों को साकार किया।

अगले छह दिनों तक चलने वाले इस शिविर में अनेक सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी, जिससे छात्राओं को समाज सेवा और नेतृत्व क्षमता का अनुभव प्राप्त होगा।

क्रांतिनायक धनसिंह कोतवाल शोध संस्थान 51 महिलाओं को करेगा सम्मानित



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बागपत। क्रांतिनायक धनसिंह कोतवाल शोध संस्थान के चेयरमैन तस्वीर सिंह चपराना ने बताया कि नारी शक्ति सम्मान 2025 के लिए निर्णायक मंडल द्वारा 51 महिलाओं का चयन हुआ है।

इन महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी शक्ति सम्मान से 7 मार्च को आईएमए हाल मेरठ में कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित किया जाएगा। चेयरमैन तस्वीर सिंह चपराना ने बताया कि नारी

शक्ति सम्मान 2025 के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह कपूर राष्ट्रपति पदक से अलंकृत, डॉक्टर रेनू जैन विभाग अध्यक्ष इतिहास सदस्या चयन समिति, प्रोफेसर डॉक्टर किरण प्रदीप प्राचार्या सदस्या चयन समिति, अर्शा जे बिलफ्रेंड प्रधानाचार्या सदस्या चयन समिति, रितु मांगलिक सदस्या चयन समिति ने बड़ी सुझबुझ से इस चयनकार्य को संपन्न किया है। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सरबजीत सिंह कपूर ने बताया कि यह वह

महिलाएं हैं, जिन्होंने क्रांतिनायक धनसिंह कोतवाल तथा अन्य क्रांतिकारी पर शोध कार्य, शिक्षा उत्थान, खेल, चिकित्सा, व्यवसाय, कृषि, स्वच्छता, कला, विज्ञान, प्रबंधन, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट प्रेरणादायक कार्य किया है। प्रेस वार्ता में निर्णायक मंडल के पदाधिकारी एवं डॉ उमेश कुमार पटेल, प्रधानाचार्य संजीव कुमार नागर, इंजीनियर अनिल राणा, पूर्व इंसपेक्टर चेतन सिंह धामा आदि उपस्थित रहे।

भाजपा नेता सुन्दर धामा को किया सरबजीत कौर जन सेवा सम्मान से सम्मानित

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बागपत। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया लोकसभा संयोजक एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुन्दर धामा को सरबजीत कौर जन सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसको लेकर उन्होंने सरबजीत कौर का आभार व्यक्त किया है।

सुन्दर धामा भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूरसंचार सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य हैं। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया जाता है, ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके अलावा उनके द्वारा समय-समय पर कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं।सुप्रसिद्ध समाज



सेविका सरबजीत कौर की तरफ से उनके प्रतिनिधि विपुल जैन ने सुन्दर धामा को सरबजीत कौर जन सेवा सम्मान देकर सम्मानित किया। सरबजीत कौर जन सेवा सम्मान समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोगों, विशेष प्रतिभाओं, खेल-खिलाड़ियों तथा मेधावी छात्र-छात्राओं

के उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है, ताकि अन्य लोग भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर देश व समाज सम्मान देकर सम्मानित किया सके। विपुल जैन ने कहा कि आगे भी समाज की ऐसी प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग उत्पाद जागरूकता हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। जन सामान्य को आत्मनिर्भर एवं स्वालम्बन बनाने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग उत्पाद जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत काष्ठ कला परिसर निकट विकास भवन आज एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जागरूकता शिविर में उपस्थित हुये आई.टी.आई. के विभिन्न ट्रेडों के छात्र/ छात्राओं एवं बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को विभाग द्वारा से संबंधित योजनाओं की विस्तृत संचालित योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री



ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं व उ०प्र० माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित माटीकला उद्योग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी के साथ-साथ बैंकों के

माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन करने से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रों सहित समस्त जानकारी प्रदान की गयी।

जागरूकता कार्यक्रम में सहायक आयुक्त (उद्योग) अर्चना पालीवाल

द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। सहायक अग्रणी बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा साक्षी द्वारा सरकारी योजनाओं के ऋण सुविधा एवं वित्तीय प्रबन्धन पर जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस अवसर पर जिला/परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय स्टाफ, सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना पालीवाल, कार्यदेशक आई.टी.आई. भूपेन्द्र शर्मा सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस लाइन में घुसे दंगाई, किया पथराव, आगजनी

मॉकड्रिल के दौरान पुलिस फोर्स ने एक को किया ढेर

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में बुधवार की सुबह अचानक बड़ी तादात में बलवाई और दंगाई घुस गए। अंदर घुसते ही पुलिस पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी शुरू कर दी। जिससे पुलिस लाइन में अफरा-तफरी मच गई। इस मंजर ने पुलिसकर्मियों के बीच बेचैनी बढ़ा दी। पुलिस कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में एक दंगाई को ढेर कर दिया, जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद सभी दंगाई वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिसकर्मियों को तब राहत का एहसास हुआ जब उनको इस बात का पता चला कि यह दंगाई और बलवाई असली नहीं बल्कि नकली हैं। इस मौके पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बता दें कि होली के

मदेनजर एसएसपी ने दंगाईयों के खिलाफ पुलिस का रिहर्सल कराया। जिसमें अचानक एक दर्जन के करीब दंगाई परेड ग्राउंड में पहुंचते हैं। जहां पर बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे पुलिस टीम के साथ दंगाइयों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन, दंगाई पुलिस को देख कर पुलिस के खिलाफ एक साथ नारे लगाने शुरू कर देते हैं। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी दंगाई बात करने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने विरोध किया तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस टीम ने आंसु गैस के गोले छोड़े हुए लाठी चार्ज कर दी। लेकिन, दंगाई ने इतने में फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक दंगाई को ढेर कर दिया। जबकि,

एक दंगाई गंभीर रूप से घायल हो गया और बाकी सभी उपद्रवी वहां से फरार हो गए।

हालाकि, पुलिस को पता चला कि यह कोई दंगाई नहीं है। बल्कि, उन्हीं के साथी पुलिस कर्मी हैं और यहां कोई बवाल नहीं बल्की मॉक ड्रिल हो रहा था। जिसे देख एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस कर्मचारियों की प्रशंसा की। इस दौरान फायर ब्रिगेड भी पुलिस लाइन ग्राउंड में मौजूद थीं। जिससे आगजनी की घटना पर काबू पाया जा सके। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इसमें पुलिस कर्मियों को बलवाइयों को रोकने के गुर सिखाए गए। एसएसपी ने इस दौरान पुलिस कर्मियों से गोलियां भी चलवाई, जिसमें कई पुलिस कर्मी गोली नहीं चला सके।

स्मार्ट सिटी का वाडों को जीरो वेस्ट बनाने पर रहेगा जोर :सीईओ संजीव कुमार मौर्य

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में निर्माण कार्य नहीं कराए जाएंगे। वाडों को वेस्ट बनाने पर काम किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होगा। बरेली में सबसे अधिक सफाई के लिए संसाधन विकसित करने की तैयारी है।

पहले चरण में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी वाडों को सफाई के मामले में स्मार्ट बनाएगी। इसके तहत जीरो वेस्ट की योजना बनाई गई है। जिसके तहत वाडों में लोगों को गीले कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मानव संसाधनों को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूह और एनजीओ का सहयोग लिया जाएगा। इससे डीजल और मानव श्रम को बचत होगी। इसके लेकर इन दिनों स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की एक कार्यशाला जयपुर में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्ोवेट इंटीग्रेटेड

एंड सरटेन चैलेंज के तहत चल रही है। पहले दिन स्मार्ट सिटी के सीईओ संजीव मौर्य ने सर्कुलर इकोनॉमी और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की कार्ययोजना स्वच्छता और श्री आर (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल) और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित है। इसमें विदेशी एजेंसियों के सहयोग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर पूरा जोर दिया जाएगा। कूड़ा निस्तारण को लेकर योजना तैयार की गई है। आधुनिक सफाई उपकरणों की होगी खरीदारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के सीईओ संजीव कुमार मौर्य के अनुसार दूसरे दिन कार्यशाला में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

नारी शक्ति के लिए प्रेरणा बनीं आईपीएस अंशिका वर्मा

बरेली । एसपी साउथ की जिम्मेदारी संभाल रहीं आईपीएस अंशिका वर्मा को बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित पांचवें वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में कई देशों से आई महिलाओं के बीच आईपीएस अंशिका वर्मा ने पुलिस के काम की चुनौतियों को बताया।

इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंशिका वर्मा के कामों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के



उद्देश्य से आयोजित शिखर सम्मेलन में महिला दिवस मनाया गया। इसमें आईपीएस अंशिका वर्मा को वुमेन ऑइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया।

अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस हैं। वह मूलरूप से प्रयागराज की निवासी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद

बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और सफलता पाई। गोरखपुर में करीब 10 माह के कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अंशिका वर्मा को प्रमोशन देकर बरेली का एसपी साउथ बनाया है। बरेली में वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं।

आवंटन अब बीयर और शराब एक ही दुकान पर बिकेगी

आज होगा ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन

एनपीटी ब्यूरो

बरेली। अब एक ही दुकान से ठंडी बीयर और विदेशी शराब की बिक्री होगी। इसके लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। उससे पहले छह मार्च को बरेली में 160 कंपोजिट दुकानों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से होगा।

जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि शराब के शौकीनों की सुविधा और बिक्री की लागत को कम करने के लिए नई



आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था की गई है। अब बीयर

और विदेशी शराब की सभी दुकानों को कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा।

ऐसे 160 कंपोजिट लाइसेंस पूरे जनपद में आवंटित किए जाएंगे। यहां होनी है ई-लॉटरी डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए यह ई-लॉटरी सुबह 10 बजे से संजय कम्युनिटी हॉल रामपुर गार्डन में होनी है। सभी आवेदकों को पंजीकरण स्लिप के साथ सुबह नौ बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। ई-लॉटरी प्रमुख सचिव सहकारिता और बरेली के नोडल अधिकारी सौरभ बाबू की निगरानी में कराई जानी है।

संपादकीय

व्यवस्थागत त्रास झेलते हरियाणा के स्कूल

हरियाणा के सरकारी स्कूल जिस बदहाली से गुजर रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है कि ये स्कूल बीमार भविष्य के कारखाने साबित हो सकते हैं। हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए युक्तीकरण के प्रयासों से राज्य में सार्वजनिक शिक्षा की निराशाजनक स्थिति ही उजागर हुई है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में 487 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बिना किसी शिक्षक के संचालित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विडंबना यह है कि करीब 294 स्कूलों में कोई छात्र नामांकित नहीं है। निश्चय की छात्रों के मोहभंग के कारणों को समझना कठिन नहीं है। निश्चित रूप से यदि प्राथमिक शिक्षा की यह तस्वीर है तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। विडंबना यह भी है कि शिक्षा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की कवायद में शिक्षकों की बड़ी कमी के बावजूद पांच हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो गए हैं। हालांकि, छात्र-शिक्षक अनुपात 28:1 प्रबंधनीय लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब है। लगभग 16,500 से अधिक टीजीटी और 11,341 पीजीटी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं राज्य के विश्वविद्यालय और कालेज भी शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यहां तक कि सरकारी कॉलेजों में भी व्याख्याताओं के लगभग आधी पद खाली हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि राज्य में योग्य बेरोजगारों की बड़ी संख्या के बावजूद ये पद खाली पड़े हैं। जो व्यवस्थागत खामियों की ओर ही इशारा करते हैं। विसंगति यह भी है कि बजटीय उपेक्षा ने समस्या को और बढ़ा दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक संबंधित मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आवंटित बजट का समय रहते उपयोग न कर पाने के कारण शिक्षा निधि में 10,675 करोड़ रुपये वापस लौटने का उल्लेख किया था। जो शिक्षा विभाग की उदासीनता की ही तस्वीर ही उकेरता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक ओर वित्तीय संसाधनों की कमी की बात कही जाती है और दूसरी ओर शिक्षा निधि में उपयोग न किए गए धन को लौटाने की बात सामने आ रही है। जाहिरा तौर पर यदि आवंटित धन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का दावा निरर्थक ही साबित होगा। कमोवेश शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाये जाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों का अंकगणितीय ज्ञान और साक्षरता का कौशल पंजाब व पड़ोसी राज्य हिमाचल से कमतर ही है। हाल में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी एएसईआर 2024 एक गंभीर स्थिति को ही उजागर करती है। वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि ग्रामीण स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के केवल 43.1 प्रतिशत छात्र ही गणित में भाग की गणनाएं कर सकते हैं। जो कि वर्ष 2022 में 49.5 प्रतिशत से कम ही है। जबकि दूसरी ओर पंजाब के स्कूलों के छात्र 58 फीसदी के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 44 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर पढ़ने का कौशल भी उतना ही चिंताजनक है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र गिरावट का ट्रेंड ही नजर आएगा। जाहिर है इससे छात्रों का ही नुकसान होगा। दरअसल, शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को संबोधित करने की जरूरत है। निस्संदेह, सरकारी स्कूलों में समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों की ही अधिकता होती है। समाज के वंचित वर्ग के छात्र भी बड़ी संख्या में इन स्कूलों में दाखिले लेते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि अभिभावक की छात्रों के उन्नयन में आपेक्षित भूमिका नहीं हो पाती। ऐसे में शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की जरूरत तो है ही, साथ ही शिक्षा विभाग को भी व्यवस्थागत विसंगतियों को दूर करने के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। सरकार को भी शिक्षक-छात्र अनुपात को न्यायसंगत बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन कारणों की भी पड़ताल हो जिनकी वजह से छात्रों का सरकारी स्कूलों में प्रदर्शन निराशाजनक बना हुआ है।

संसदीय सीटों के परिसीमन के यश प्रश्न

दक्षिणी राजनेताओं का तर्क है कि परिसीमन से राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज और उपस्थिति कम होगी। उन्हें आर्थिक और सामाजिक-विकास का पुरस्कार मिलने के बजाय सजा मिलेगी। निस्संदेह, देश के विकास में क्षेत्रीय-असंतुलन के ऐतिहासिक-कारणों को समझते हुए भविष्य की संभावनाओं को भी देखना होगा।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश के राजनेताओं और विक्षेपकों के एक तबके ने दो-तीन बातों पर जोर देना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र विफल हो रहा है और यह भी कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतना भर नहीं होता। लोकतंत्र ही नहीं, संघवाद को भी खतरे में बताया जा रहा है। बीजेपी के हिंदू-राष्ट्रवाद की अतिशय केन्द्रीय-सत्ता को लेकर भी उनकी आपत्तियां हैं।

इधर तमिलनाडु से हिंदी-साम्राज्यवाद को लेकर बहस फिर से शुरू हुई है, जिसमें संसदीय-सीटों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां भी शामिल हैं। दक्षिण के नेताओं का तर्क है कि यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, तब दक्षिण के राज्य नुकसान में रहेंगे, जबकि जनसंख्या-नियंत्रण में उनका योगदान उत्तर के राज्यों से बेहतर रहा है। उनका सुझाव है कि संसदीय परिसीमन में संघवाद के मूल्यों का अनुपालन होना चाहिए।

परिसीमन से जुड़े इन्हीं सवालों को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 5 मार्च को चेन्नई में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा- तमिलनाडु अपने अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। परिसीमन का खतरा दक्षिणी राज्यों पर डेमोकलीज की तलवार की तरह मंडरा रहा है। मानव विकास सूचकांक में अग्रणी तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरा खड़ा है।

उनका यह भी कहना है कि अभी तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन की प्रक्रिया से इनकी संख्या घटकर 31 रह जाने की संभावना है। बात सिर्फ संख्या में कमी की नहीं है, यह हमारे अधिकारों का मामला है। स्टालिन के इस बयान के फौरन बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को एक भी सीट नहीं गंवानी पड़ेगी। उन्होंने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की लंबे समय से चली आ रही इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि यदि नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा।

हालांकि इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन करना होगा, पर आज जो बातें हो रही हैं, वे कयासों और अटकलों पर आधारित हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके विभाजन को फिर से समायोजित किया जाएगा। यह परिसीमन प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वही एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को ह्यमियां-टियांल्ल और ह्यपाकिस्तानील्ल शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप-मुक्त कर दिया कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शब्दों के प्रयोग को गैर-मुनासिब माना। एक दूसरे रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अश्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार-सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अश्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पांडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े मुकदमों रूपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए।

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन ह्यमियां-टियांल्ल और ह्यपाकिस्तानील्ल जैसे शब्दों से जुड़े मुकदमे को



निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय करने में लगभग चार साल लगे, मगर दोनों पक्षों ने किसी पड़ाव पर यह समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं की कि यह सिर्फ अहं की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मान्यने रखती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, इंसाफ और इश्क की बात करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समुदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तलख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की

रक्षा कौन करेगा ?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सीख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदगी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द-सद्भावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हों।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की

नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी औछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अश्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह ऐसे समय सामने आया है जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विभिन्न समुदायों का विचलन, द्वेष एवं नफरत काफी बढ़ी हुई दिख रही है। शासन प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने की कोशिशों में भी अक्सर अति-उत्साह की झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया के ये मंच स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भूमिका भी निभाते देखे जाते रहे हैं। उन पर कड़ाई से बहुत सारे ऐसे लोगों के अधिकार भी बाधित होने का खतरा है, जो स्वस्थ तरीके से अपने विचार रखते

और कई विचारणीय मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। मगर जिस तरह बड़ी संख्या में वहां उपद्रवी, हिंसक, राष्ट्रीय और सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करने वाले तत्त्व सक्रिय हो गए हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। इससे जहां नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल की बेजा स्थितियां भी देखने को मिलती है। शीर्ष अदालत ने याद दिलाया है कि इस अधिकार का ख्याल रखा जाए। उन पर अंकुश लगाने एवं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करना जरूरी है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के विरुद्ध वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। सरकार इनकी रक्षा के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ-साथ सेंसरशिप के प्रति अपनी अनिच्छा को दोहराया। लेकिन यह भी कहा कि ऐसा विचार ह्यघटिया विचारोंल्ल और ह्यगंदी बातोंल्ल का लाइसेंस नहीं है। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया में जिस पैमाने पर विष-वमन हो रहा है, उसने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। मगर उसकी कार्रवाइयां इसलिए प्रभावी नहीं होतीं, क्योंकि राज्य-दर-राज्य उनके पीछे के राजनीतिक पक्षपात भी स्पष्ट हो जाते हैं। राज्य पुलिस अक्सर सरकार विरोधी पोस्ट के मामलों को तो तत्परता दिखाती है, मगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की वैसी ही गतिविधियां वह नजरअंदाज कर देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही गुजरात पुलिस को एहसास कराया है कि उसे असामाजिक तत्वों से निपटते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा भी करनी है। जाहिर है, उच्छृंखल हुए बिना आजादी के उपयोग में ही नागरिक का भी भला है और समाज का भी।



इस तरह की कवायद 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद की गई थी। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। वर्ष 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 494, 522 और 543 तय की गई थी, जब जनसंख्या क्रमशः 36.1, 43.9 और 54.8 करोड़ थी। इसका मोटे तौर पर मतलब है कि प्रत्येक सीट पर औसतन क्रमशः 7.3, 8.4 और 10.1 लाख आबादी थी। जनसंख्या-नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 1971 की जनगणना के बाद से इसे स्थिर रखा गया है ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो। यह कार्य 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहले वर्ष 2000 तक के लिए किया गया था। फिर 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था। अभी जिस जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तय है, वह 1971 की जनगणना के अनुसार है। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर इस संख्या को फिर से समायोजित किया जाएगा। अभी लगता नहीं कि 2026 के पहले वह जनगणना हो भी पाएगी या नहीं, जिसे 2021 में होना था। यह देखते हुए कि विधायिका में महिलाओं का आरक्षण भी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है, इसमें देरी दिक्कत पैदा करेगी। राज्यों में भी जनसंख्या वृद्धि में समतुल्यता के लिए सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के अनुरूप फ्रीज कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया था कि परिसीमन

की कवायद साल 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होगी। बहरहाल, पहले इस बात पर विचार करना होगा कि परिसीमन की नई प्रक्रिया में केवल राज्य की जनसंख्या का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा या नहीं। आनुपातिक संख्या पर नजर डालें, तो तमिलनाडु की यह चिंता जायज है। थोड़ी देर के लिए तमिलनाडु और अविभाजित बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दरों (1971-2024) में अंतर देखा जा सकता है। मतदाताओं की संख्या के जो नवीनतम अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार अविभाजित बिहार में 233 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि तमिलनाडु में 171 फीसदी। 1971 की जनगणना के आधार पर 1977 की लोकसभा में भारत के प्रत्येक सांसद ने औसतन 10.11 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया। इसी औसत को आज की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर रखेंगे, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या करीब 1,400 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यूपी (उत्तराखंड सहित) की सीटें करीब त्रिगुनी हो जाएंगी, अर्थात 250 तक और बिहार (झारखंड सहित) में 169 हो जाएगी। तमिलनाडु की वर्तमान 39 से बढ़कर 76 और केरल में 20 से बढ़कर 36 होंगी। पर यह औसत अब काम नहीं करेगा। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, इसलिए यह फॉर्मूला भी बदलेगा। यह औसत 15 लाख होगा या 20 लाख या कुछ और। दक्षिणी राजनीति का तर्क है कि परिसीमन से राष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज और उपस्थिति कम होगी। उन्हें आर्थिक और सामाजिक-विकास का पुरस्कार मिलने के बजाय सजा मिलेगी। यह तर्क गलत नहीं है, पर देश के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के ऐतिहासिक कारणों को भी समझना होगा और भविष्य की संभावनाओं को भी देखना होगा। दक्षिण के राज्यों की लाभकारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां पूंजी-निवेश बेहतर हुआ है। यह सारी पूंजी उसी इलाके में संचित नहीं थी, बाहर से भी आई है। आज भी इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बंदरगाहों और राजमार्गों की परियोजनाओं पर पूंजी निवेश वहां की स्थिति के आधार पर हो रहा है। इन परियोजनाओं और उद्योगों में काम करने के लिए श्रम-शक्ति भी बाहर से आई। क्षेत्रीय सम्पन्नता ने इस इलाके में शिक्षा, सार्वजनिक-स्वास्थ्य और सामाजिक-जागरूकता को बढ़ाने में सहयोग किया है। मोटा अनुमान है कि देश में करीब 14 करोड़ प्रवासी मजदूर काम करते हैं। कोविड-19 के दौरान हमने इन मजदूरों के परिवहन से जुड़ी समस्याओं को देखा था। इनमें सब लोग उत्तर से दक्षिण या पश्चिम में ही नहीं जाते हैं। दक्षिण से उत्तर आने वाले लोग भी हैं, जो अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर बेहतर जीवन-यापन के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आधुनिक औद्योगिक-तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण कारक प्रवासन भी है। बेशक दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए, पर ऐसे समाधान तभी संभव है, जब हम तुच्छ राजनीति को अलग रखेंगे। यह राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसका समाधान भी राष्ट्रीय ही होगा।

यूपी विधानसभा: अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए दोनों सदन, 72 घंटे 56 मिनट तक चली विधानसभा

लखनऊ । यूपी विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही कुल 72 घंटे 56 मिनट तक चली। यूपी विधानसभा का बजट सत्र पूरा हो गया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही कुल 72 घंटे 56 मिनट तक चली। जबकि 3 घंटा 36 मिनट के लिए स्थगित हुई। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन चर्चा हुई। इसमें 147 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट पर साधारण चर्चा 4 दिन तक हुई। जिसमें कुल 94 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 3 विधेयक पारित हुए। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुख्यमंत्री नेता सदन योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और समेत सभी दलीय नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य इस सदन का ब्रांड एम्बेसडर है। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सदन में सदस्य जो भी वायदा अपने क्षेत्र में करें उसे पूरा जरूर करें। वरना इससे साख गिरेगी। उन्होंने कहा कि विधायक पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करें। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई तकनीक होने से विधानसभा की कार्यवाही में सभी विधायकों को काफी सहयोग मिल रहा है।

आक्रामक कुत्तों से सम्बन्धित समस्या के लिए बीडीओ व पशु चिकित्साधिकारियों को करें सूचित-डीएम

बहराइच। जिले में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपदवासियों से अपील की है कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें तथा परिवार के छोटे बच्चों को अकेले जाने आने न दें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में यदि आक्रामक कुत्तों एवं बन्दरों इत्यादि से सम्बन्धित कोई समस्या है तो तत्काल सम्बन्धित क्षेत्र के नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं पशु चिकित्साधिकारियों के मोबाइल नम्बर पर इसकी सूचना अवश्य दें। विकास खण्ड मिर्हीपुरवा हेतु मो.न. 9454464805, नवाबगंज हेतु मो.नं. 9454464806, बलहा हेतु मो.नं. 9454464807, शिवपुर हेतु मो.नं. 9454464808, रिसिया हेतु मो.नं. 9454464809, चितौरा हेतु मो.नं. 9454464810, महसी हेतु मो.नं. 9454464811, तेजवापुर हेतु मो.नं. 9454464812, फखरपुर हेतु मो.नं. 9454464813, हुजूरपुर हेतु मो.नं. 9454464814, कैसरगंज हेतु मो.नं. 9454464815, जरवल हेतु मो.नं. 9454464816, विशेष्वरगंज हेतु मो.नं. 9454464817 एवं पयागपुर हेतु मो.नं. 9454464818 पर सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बहराइच व नगर पंचायत पयागपुर हेतु मो.नं. 8189078341, नगर पालिका परिषद नानपारा व नगर पंचायत रूपईडीहा हेतु मो.नं. 8189078342, नगर पंचायत जरवल हेतु मो.नं. 9415247856, कैसरगंज हेतु मो.नं. 9026966884, रिसिया हेतु मो.नं. 9454416033 तथा नगर पंचायत मिर्हीपुरवा हेतु मो.नं. 9140756213 पर सूचित किया जा सकता है।

कलश यात्रा के साथ सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा आरम्भ

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

महसी (बहराइच)। तहसील महसी के ग्राम पंचायत वीरशाहपुर के मजरा एडौरा स्थित ब्रह्मचारी हनुमान मंदिर में बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया गया।

कलश यात्रा वीरशाहपुर के एडौरा मंदिर परिसर से शुरू होकर बडनापुर ठाकुर द्वारा तक गई। वहां से

सरकारी जमीन पर लगी मूर्तियों दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से हटाई

शाहाबाद क्षेत्र के गुलड़िया गांव में 24 घंटे पुलिस का पहरा

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

उत्तर प्रदेश रामपुर शाहबाद प्रशासन मंगलवार देर रात को गुलड़िया गांव में बिना अनुमति लगाई गई डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटवा दिया। जिसके बाद बुधवार को गांव में पुलिस का पहरा रहा। दो सिपाहियों की ड्यूटी चौबीसों घंटे लगाई गई है।बताते चले कि थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव में दो वर्गों ने बिना प्रशासन से अनुमति लिए सरकारी जमीन पर बालाजी और अंबेडकर की प्रतिमाएं लगा दी थी। प्रतिमाएं लगने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मंगलवार को एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, सीओ हर्षिता सिंह, तहसीलदार राकेश चंद्रा और कोतवाल पंकज

महिलाएं कलश में जल भरकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर वापस मंदिर परिसर पहुंचीं। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीला वस्त्र पहने व सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीतों पर थिरकती नजर आईं। कार्यक्रम के मुख्य यजमान शिवकुमार शुक्ला व लक्ष्मी देवी हाथ में कलश लेकर यात्रा के आगे-आगे चलते रहे। कार्यक्रम के आयोजक व मुख्य यजमान

पंत ने गांव पहुंचकर दोनों वर्गों को समझाकर प्रतिमाएं हटाने को कहा। जिस पर एक पक्ष के लोगों ने मंगलवार दिन में ही बालाजी की प्रतिमा को हटाकर गमादेव पर रख दिया जबकि अंबेडकर की प्रतिमा हटाने के विरोध में दलितों की महिलाएं आगे आ गई और प्रतिमा हटाने पर गांव छोड़ने तक की चेतावनी दे डाली। प्रशासन ने लोगों को समझाते हुए स्वयं प्रतिमा हटाने को कहा अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। इसी गहमागहमी के बीच लोगों ने प्रशासन की मौजूदगी में रात दस बजे स्वयं ही अंबेडकर की प्रतिमा हटा ली। दोनों प्रतिमाएं हटने के प्रशासन ने राहत की सांस ली। उधर दोनों स्थानों पर बुधवार को भी पुलिस का पहरा रहा।



शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि ऐसे महान धार्मिक कार्य का सौभाग्य पाकर धन्य महसूस कर रहा हूं। भागवत भगवान की कृपा मेरे सभी ग्राम वासियों व क्षेत्र वासियों

बिना सुरक्षा संकलन केंद्र तक लाई जा रही उत्तर पुस्तिकाएं

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक लाने में मानकों की अनदेखी की जा रही है। हाल यह है इन्हें बाइक व स्कूटी से बिना सुरक्षा के संकलन केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है।

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हुईं। इसमे पहले दिन से ही लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिन्हें देखकर लग रहा है कि मथुरा में विभागीय जिम्मेदार नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। एक ओर एसटीएफ और एलआईयू से निगरानी की बातें कही जा रही हैं। दूसरी



ओर बिना सुरक्षा के विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र से संकलन केंद्र तक लाया जा रहा है। मंगलवार को भी परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाइक और स्कूटी से ढोकर संकलन केंद्र तक उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाई गईं। नियम यह है कि इन कॉपियों को केंद्रों तक बंद गाड़ियों से ही पहुंचाया जाए। संकलन केंद्र पर भी बिना मानकों के केंद्रों से आई कॉपियों को रिसीव किया जा

जीवन में सही राह दिखाती है।

इसलिए जहां भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इस दौरान दिलीप शुक्ला, मुकेश कुमार शुक्ला, प्रदीप कुमार शुक्ला, पंकज दीक्षित, छोटुकाका, रोहित मिश्रा,अनीता शुक्ला, रविकांत मिश्रा आदि सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

आईएस रिंकू राही बने मथुरा सदर के नए एसडीएम

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा । जिलाधिकारी सीपी सिंह ने प्रशिक्षु आईएस रिंकू राही को एसडीएम सदर के पद पर नियुक्त किया है। अब तक इस पद पर तैनात पीसीएस वैभव गुप्ता डिप्टी कलेक्टर के तौर पर कलेक्ट्रेट में कार्य देखेंगे। सूत्रों का कहना है की होली के पश्चात अन्य तहसीलों में भी बदलाव देखा जा सकता है। इनके अलावा वृंदावन नायब तहसीलदार के पद पर अनमोल गर्ग की तैनाती की गई है। बता दें कि



रिंकू सिंह राही उत्तर प्रदेश के 2007 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2007 में यूपीएससी की पीसीएस परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्हें साल 2008-09 में मुजफ्फरनगर

में समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। साल 2009 मार्च में उन्होंने 100 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति भ्रष्टाचार का खुलासा किया था।

इस दौरान कुछ माफिया पीसीएस रिंकू राही के पीछे लग गए थे। इन माफिया लोगों ने रिंकू राही पर जानलेवा हमला भी किया था। इस हमले में हमालवरों ने रिंकू पर सात गोलियां दागी थीं। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान बच गई, लेकिन उनके चेहरे का आकार बदल गया।

मथुरा-व्रन्दावन जाने वाली सड़क की राह हुई आसान



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। मथुरा-वृंदावन जाने वाले ट्रैक के स्थल पर सड़क बनने की राह आसान होती दिख रही है। मंगलवार को रेलवे के अधिकारी ट्रैक वाले स्थल से सामान हटवाते दिखे। यहां 2 साल पहले रेल लाइन का काम स्थानीय लोगों के विरोध के कारण रोक दिया गया था। सांसद हेमा मालिनी ने रेलवे की जमीन पर सड़क बनाने की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था। जिस पर उन्होंने सहमति दे दी थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार से सौख तिराहे के पास रखा रेलवे लाइन का सामान हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुराना सामान स्टोर में जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन की भूमि पर सड़क बनाने की चर्चा चल रही है इसलिए रेलवे अपना सामान

हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर कई महीनों से ऐसा ही रेलवे का सामान रखा है उन्होंने कहा कि लोगों ने रेल लाइन नहीं बिछाने को लेकर विरोध किया था, अगर लाइन यहां पर बिछ जाती तो लोगों को काफी परेशानी होती। सौख के पास रहने वाले सुखदेव ने कहा कि मथुरा-वृंदावन 12 किलोमीटर मार्ग पर रेल लाइन की जरूरत पहले से ही नहीं थी, लेकिन रेलवे अधिकारी लाइन बिछाने पर लगे हुए थे।

रामप्रकाश का कहना है कि अब सांसद की पहल के बाद सामान हटना शुरू हुआ है इससे यह स्पष्ट होता है कि अब यहां पर सड़क बनने की राह आसान हो गई। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे विभाग अपना सामान हटाकर दूसरे जगह रख रहा होगा।

सैफनी में भारतीय गौ रक्षा वाहिनी का किया गया विस्तार हाफिज मुबारक अली को प्रदेश मंत्री बनाया

उत्तर प्रदेश रामपुर।बुधवार को नगर पंचायत सैफनी में पुरानी कब्राला के निकट नई बस्ती में भारतीय गौ रक्षा वाहिनी का किया गया विस्तार और भारतीय गौ रक्षा वाहिनी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री हाफिज मुबारक अली के आवास पर फूलमाला पहनकर स्वागत किया गया और गौ रक्षा अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह लोधी ने बताया कि हमारी टीम सराहनीय काम कर रही है अगर गौ माता बीमार पड़ती है तो टीम तुरंत पहुंचकर गाय का उपचार



करती हैं और इधर-उधर घूम रही गायों को भेजने का भी कार्य करती हैं हाफिज मुबारक अली को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की और गौ रक्षा कैसे की जाए

इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस अवसर पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के युनुस अंसारी, सैयद वारिस अली, गुड्डू भाई,, डॉक्टर,जावेद अख्तर दो फरदीन अहमद आदि लोग उपस्थित रहे

कुत्ते नौचकर खा रहे थे मृत गोवंश

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। बाजना नगर पंचायत में बनाई गई अस्थाई गोशाला के हालात खराब हैं। देखरेख के अभाव में यहां गोवंश की दुर्गति हो रही है, वे दम तोड़ रहे हैं। मृत गोवंश का शव कुत्ते नौचकर खा रहे हैं। एक सभासद ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरकत में आए पंचायत प्रशासन ने लापरवाही पर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। उनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सभासद हेमराज ने बताया कि अस्थाई गोशाला में कई दिन से गोवंश बीमार चल रहे हैं। इनमें से एक गाय की मौत हो गई। कर्मचारियों ने शव को जमीन में दबाने के बजाए



गोशाला में एक किनारे फेंक दिया। कुत्तों ने उसको अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया। सूचना पर अन्य सभासद मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। सभासद गौरव ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

सूचना पर ईओ जितेंद्र सिंह ने मौके पर कर्मचारियों को भेजा। पशु अस्पताल

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बहराइच। जनपद में कुत्तों एवं बंदरों के हमलों पर प्रभावी अंकुश तथा पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु मंगलवार को देर शाम जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान वरचुंअली प्रतिभाग कर रहे नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं पशु चिकित्साधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में अभियान चलाकर हमलावर कुत्तों के बध्याकरण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि



सामुदायिक चिकित्सालयों के डाटा का अध्ययन कर अति संवेदनशील एवं संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन कर तदनुसार कार्यवाही की जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जाय। लोगों को बताया जाय कि वह अपने परिवार के बच्चों को अकेले खेतों की ओर न जाने दें। डीएम ने कहाकि सम्बन्धित अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर जमीनी स्तर पर समस्या का पता लगाकर उसका निस्तारण करायें। बैठक में जानकारी दी गई कि सदर अन्तर्गत 279, तेजवापुर

में 323, मिर्हीपुरवा में 345, रिसिया में 391, महसी में 379, शिवपुर 439, फखरपुर में 299, चितौरा में 322, जरवल में 421, पयागपुर 372, बलहा में 224, कैसरगंज में 375, नवाबगंज में 361, हुजूरपुर में 237 एवं विशेष्वरगंज में 268 इस प्रकार जिले में 5035 लोगों को रैबीज के इन्वेन्शन लगाये गये हैं।

डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों एवं बंदरों आदि से बचाव में कूड़ा प्रबंधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां पर कूड़े में खाने पीने की सामग्री की

अधिकता होती है, वहां प्रायः आवारा पशुओं की संख्या बढ़ जाती है।

अतः कूड़े का नियमित उठान और पृथक्कीकरण आवश्यक है। बैठक के माध्यम से डीएम ने सभी जनपदवासियों से अपील की कि वह अपने क्षेत्र के हमलावर कुत्तों बंदरों अथवा अन्य पशुओं के संबंध में संबंधित बीडीओ, ईओ व पशु चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल सूचना उपलब्ध करायें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अप्रर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने सूबे के

डिप्टी सीएम से मिल मेडीकल कॉलेज में

अल्ट्रासाउंड मशीन को बढ़ाने की भी रखी बात

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर
ललितपुर जनपद की विधानसभा महारौनी से विधायक व राज्य मंत्री ने मनोहर लाल पंथ ने सूबे के उपमुख्यमंत्री व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चिकित्सा व्यवस्था सुधार के लिए विभिन्न मांगो के साथ एक पत्र भी दिया। जिसमें उन्होंने जनपद के मेडिकल कालेज में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मरीजों को अस्पताल में भीड़ के कारण लम्बी तारीख दी जा रही है, जिससे परेशान होकर मरीज प्राईवेट कराना पसंद कर रहा है। यदि अल्ट्रासाउंड मशीनों की



संख्या बढ़ा दी जाए तो काफी हद तक यह समस्या का निदान हो जाएगा। मरीजों एवं तीमारदारों को उपचार

कराने में काफी असुविधा हो रही है, मरीजों के लिए इमरजेन्सी कक्ष में इमरजेन्सी बैड की संख्या में बढ़ोतरी

कराया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय मेडिकल कालेज के अधीन संचालित हो रहा है, जिससे चिकित्सालय की स्थिति में अत्यधिक सुधार आना चाहिए था। इसी के साथ राज्य मंत्री ने एमआरआई की मशीन न होने के कारण टेस्ट प्राईवेट जगह कराने को मजबूर होते है, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी असुविधा होती है। जिला चिकित्सालय में उक्त सुविधा को चालू कराये जाने का प्रस्ताव रखा जिस पर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन कराया।

नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनपद स्तरीय

खेल प्रतियोगिता का आयोजन

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर
नेहरू युवा केन्द्र ललितपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय पनारी ललितपुर के क़िड़ग़ान में जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खण्ड स्तर के विजेताओ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य जाखलौन श्री अमर विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि उप प्राचार्य पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय श्री प्रकाश खरे तथा विकास चौरसिया लेखा एवं कार्यक्रम

सहायक नेहरू युवा केन्द्र ललितपुर ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण कर किया । कबड्डी प्रतियोगिता में दैलवारा, बिरधा तथा महरौनी ने क्रमशः क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया । वालीबाल प्रतियोगिता में बारचौन, बिरधा तथा पवा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया । 400 मीटर की रेस में प्रियांशु सिंह, लालू प्रसाद तथा पृथ्वी सिंह चौहान ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया । सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना का प्रदर्शन किया । प्रतियोगिता के समापन

पर विजेता और उपविजेता टीमों को स्मृती चिह्न तथा मेडल दे कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने युवाओं की मेहनत और खेल भावना की सराहना की और उन्हें आगे भी अपनी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया । कार्यक्रम में प्रमुख रुप से फ्युचर फारवर्ड फाउण्डेशन के सचिव के निर्णायक के रुप में सुख साहब यादव, आशीष दुबे और श्री राजेश राय उपस्थित रहे एवं नेहरू युवा केंद्र के लेखा एवं कार्यक्रम सहायक विकास चौरसिया ने आभार व्यक्त किया ।

पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय

विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने सौंपा ज्ञापन

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर
ललितपुर विगत दिनों पूर्व मेडिकल कॉलेज ललितपुर के महिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और इलाज के अभाव मे प्रसूता मालती सोनी की मृत्यु हो गई थी जिसके सम्बन्ध मे आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने जिला अध्यक्ष महेंद्र झा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम महारौनी को सौंपा।ज्ञापन मे दोषी डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को



न्याय दिलाने और परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई।ज्ञापन देते समय बैरो प्रसाद विश्वकर्मा हरिशंकर सोनी अवध बिहारी झा अमृतलाल विश्वकर्मा लक्ष्मी नारायण ताम्रकार मनोज झा प्यारे लाल विश्वकर्मा राजेश झा मनीष झा महेश झा सौरभ झा अमृत

लाल झा एडवोकेट शीतल प्रसाद विश्वकर्मा अंकित विश्वकर्मा सौरभ झा नदकिशोर विश्वकर्मा कुलदीप झा चंद्रेश झा अरविंद झा तिसगना हरिशंकर झा राकेश झा नीलेंद्र झा दीपक झा गौरव झा राजेश झा कृष्णकांत झा रामेश्वर झा अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में योग में

समग्रता विषय पर हुआ मंथन

चित्रकूट ब्यूरो: जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में योग विषय पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन बुधवार को विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडेय ने कहा कि योग जैसे समसामयिक विषय पर आयोजित होने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी निश्चित रूप से योग के नवीन आयामों को जन्म देगी। जिसके माध्यम से न केवल दैहिक बल्कि मानवीय समस्याओं का समयानुकूल समाधान संभव होगा। इस संगोष्ठी के माध्यम से देश-विदेश में योग के एक नए युग का सूत्रपात होगा। बुधवार को अमरकंटक विश्वविद्यालय के प्रो गोविंद प्रसाद मिश्र ने कहा कि प्रज्ञा अपराध जैसे अपराधों को योग के द्वारा ही निवृत्ति कर हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रज्ञावान बना सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के डॉ अम्बरीष राय



ने आसन एवं प्राणायाम के साथ वैराग्य योग एवं क्रिया योग की भी चर्चा की। कहा कि इंद्रियों का रिश्ता मन से है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधार्थी राजाराम ने पतंजलि योग एवं हठयोग में समाधि के स्वरूप पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी विशेष कुमार सिंह ने योग में समग्रता के अध्ययन विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए सामाजिक एकरूपता पर बल दिया।

पतंजलि विश्वविद्यालय के राजेश कुमार ने परंपरागत योग में प्राणायाम के अनुशीलन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संज्ञना ने प्राणायाम के महत्व एवं लाभ के बारे में अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। इस

दौरान 30 से अधिक वक्ताओं ने अपने शोध पत्रो को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के डॉ सूर्य प्रकाश ने किया। इस मौके पर संगोष्ठी के संयोजक डॉ हरिकांत मिश्र, डॉ ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ महेंद्र कुमार उपाध्याय, डॉ विनोद कुमार मिश्र, डॉ निहार रंजन मिश्र, डॉ अमित अग्निहोत्री, डॉ गुलाबधर, डॉ किरण त्रिपाठी, डॉ रजनीश कुमार सिंह, डॉ रमा सोनी, डॉ भविष्या माथुर, डॉ नीतू तिवारी, डॉ दुर्गेश कुमार मिश्र, डॉ शांत कुमार चतुर्वेदी, डॉ गोपाल कुमार मिश्र, डॉ अमिता त्रिपाठी, जितेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर निस्तारित कराएं

अधिक से अधिक वाद- जिला जज

चित्रकूट ब्यूरो: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में बुधवार को जनपद में कार्यरत समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ पंचम चरण की बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि बैठक में जनपद न्यायाधीश ने आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारण के लिए बल दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय अपराधिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम वाद, बैंक वसूली वाद, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सेवा वाद, पारिवारिक व वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व व चक्रबन्दी वाद, किरायेदारी वाद, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल वाद, राजस्व वसूली वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान व लघु अपराधिक वाद, आमवाद, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो आभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं (विशेषकर पारिवारिक मामले), उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाना है। जिला जज ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी अपने न्यायालयों से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले, जिनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है, को अधिक से अधिक चिन्हित कर उनमें पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस तामीला कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने का प्रयास करें।

जनजागरूकता अभियान के जरिए ग्रामीणों को

बताएं जंगलों को आग से बचाने के तरीके

चित्रकूट ब्यूरो: जंगलों में आग न लगे इसके लिए वन विभाग व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान प्रत्येक गांव में चला रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्युष कटियार प्रत्येक गांव का निरीक्षण कर ग्रामीणों को जंगल में आग न लगने पाए इसकी वजह बता रहे हैं उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जंगल में आग लगने से वन्यजीवों और पर्यावरण को नुकसान होता हैं। उन्होंने कहा कि आग से न केवल हरे-भरे पेड़ नष्ट हो रहे हैं, बल्कि वहां रहने वाले वन्यजीव भी प्रभावित हो रहे हैं। आग से बचने के लिए वन्य जीव सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं, जिससे उनका प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि कई बार अत्यधिक आग के कारण पुराने और दुर्लभ पेड़ जलकर राख हो जाते। जिससे पेड़ों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग एकदम अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सभी वन क्षेत्रों में वन दरोगा और वाचर महुआ बीनने वालो पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर वन संपदा अधिनियम के तहत जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग अब आधुनिक तकनीकों का सहारा भी ले रहा है। जिससे जंगलों में आग लगने की सूचना सेटेलाइट इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल इमेजिंग तकनीक के जरिए मिलने पर तत्काल आग बुझाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सेटेलाइट से प्राप्त डेटा का कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है, जिससे आग की तीव्रता, फैलाव और दिशा की जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग से निपटने के लिए वन समितियों और ग्रामीणों की मदद भी ली जा रही है। वन विभाग अपने स्तर से लोगों से अपील कर रहा है कि जंगल में आग फैलने से रोकने में सहयोग करें और किसी भी सदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

शांतिपूर्ण तरीके से मनाए होली और रमजान- डीएम

चित्रकूट ब्यूरो: शांति समिति की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्या जीएन की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें डीएम ने रमजान, होलिका दहन, होलीकोउत्सव, गुड-फ्राइडे, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, श्रीराम नवमी आदि त्योहारों को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं से वार्ता की।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 13 मार्च को होलिका दहन एवं 14 मार्च को होली का पर्व है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्र का फीडबैक लेते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। अधिशासी अधिकारी कर्वी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर को निर्देशित किया कि होलिका दहन के स्थल पर तार नहीं लटकने चाहिए। साथ ही होलिका दहन स्थल एवं मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर सफाई, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएचसी/पीएचसी पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। जल संस्थान



को निर्देशित किया कि पानी की सप्लाई लगातार रहनी चाहिए। जिला आवकारी अधिकारी को 15 मार्च तक नदी किनारे अभियान चलाकर अवैध शराब के लिए छापामारी करने के निर्देश दिए ताकि त्योहारों में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को छापामारी कर मिलावट खोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सहायक संभागीय अधिकारी को बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, पानी आदि की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि होलिका दहन के स्थल पर दो बोरा बालू व पानी की भी व्यवस्था रखें, जिससे अप्रिय घटना होने पर तत्काल निपटा जा सके।

कि अन्य संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाली कोई घटना घटित न करते हुए सभी पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाए तथा जिला प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आगामी त्योहार महत्वपूर्ण त्योहार हैं, जिसकी तैयारी भी चल रही है। कहा कि जनपद में 803 स्थलों पर होलिका दहन होना है। जहां पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कहा कि यदि समाज भी त्योहारों की जिम्मेदारी लेगा, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कहा कि पूरे रमजान तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। कहा कि होली व जुम्मा की नमाज एक ही दिन है, अतः आपस में समन्वय बनाकर एक दूसरे का सहयोग करें। होलिका आयोजन समिति को होलिका दहन स्थल पर दो बोरा बालू व पानी की भी व्यवस्था रखें, जिससे अप्रिय घटना होने पर तत्काल निपटा जा सके।

शोभा यात्रा के साथ हुई हरेश्वर

महादेव मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा

पहाड़ी, चित्रकूट: थाना पुलिसकर्मियों एवं जनसहयोग के सहयोग से हरेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य शोभायात्रा का हुआ भव्य आयोजन। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहाड़ी थाना प्रांगण में स्थानीय जन एवं पहाड़ी थाने के समस्त पुलिसकर्मियों के द्वारा हरेश्वर महादेव मंदिर स्थापना के मौके पर पहाड़ी कस्बे में भव्य शोभा निकाली गई, शोभायात्रा में पहाड़ी कस्बे वासी एवं पहाड़ी पुलिस कर्मियों ने बढ़-चढ़कर शोभा यात्रा में शामिल हुए यह शोभायात्रा पहाड़ी कस्बे के प्राचीन कटरा के देवी मंदिर में थाना प्रभारी रीता सिंह ने सापरिवार पूजा अर्चना करते हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। शोभायात्रा के दौरान पहाड़ी थाना प्रभारी रीता सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर प्रभु नाथ यादव, सब इंस्पेक्टर मनीष रावत, सब इंस्पेक्टर अकरम मोहम्मद, सब इंस्पेक्टर वैभव सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, शरद प्रताप सिंह, संतोष कुमार, व्यापार मंडल पहाड़ी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता उर्फ राजा, विनीत गुप्ता, अनीत गुप्ता पत्रकार शैलेन्द्र सिंह, पत्रकार अखिलेश दीक्षित, पत्रकार डॉ दिनेश कुशवाहा आदि शामिल हुए।

पुलिस कर्मियों से कहा कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वह होली के दिन मुस्तेदी के साथ ड्यूटी करेंगे। कहा कि लाउड स्पीकर से होली व रमजान पर निर्धारित मानक से तेज ध्वनि बजाने की अनुमति कदापि न दी जाए तथा रात 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य बजाने की अनुमति नहीं होगी। बताया कि वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 प्रभावि है। कहा बड़े-बुजुर्ग होली के दिन बच्चों को नशा करने तथा हुडडंग करने से रोके। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि किसी भी वाहन पर ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए तथा ओवरलोडिंग होने पर कार्रवाई कर वाहन सीज करें।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी पूजा साहू, मऊ सौरव यादव, मानिकपुर मोहम्मद जसीम, उपजिलाधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता देवड़ा, पुलिस क्षेत्राधिकार मऊ यामीन अहमद, राजापुर जयकरण सिंह, राजापुर नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव मिश्रा सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनूं दौरा

विद्यार्थियों से किया संवाद, नारी सशक्तिकरण पर दिया बल

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो
झुंझुनूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को झुंझुनूं दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के सांगासी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया व विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ भी उपस्थित रहीं। झुंझुनूं एयर स्ट्रिप पर जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, संभागीय आयुक्त आईएसएस पूनम, पुलिस आईजी अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया ने धनखड़ दंपति का स्वागत किया।

सांगासी में कार्यक्रम से पहले विद्यालय में उपराष्ट्रपति ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया एवं आमजन व किसानों से अपने खेतों में और घरों में पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई। इस दौरान स्कूल छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को टेबलेट की वितरित किए।

झुंझुनूं को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने जिले की दो महिलाओं कमला बेनीवाल और सुमित्रा सिंह का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कमला बेनीवाल विधायक, मंत्री और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही हैं, साथ ही गुजरात की राज्यपाल भी बनीं। वहीं, सुमित्रा सिंह कई बार विधानसभा सदस्य रहीं, मंत्री बनीं और राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष भी बनीं।



नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक कदम
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। इससे नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी होगी और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब वे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गए, तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां लड़कियां भी पढ़ेंगी। उन्होंने खुशी जाहिर की कि अब झुंझुनूं के सैनिक स्कूल में भी लड़कियों का प्रवेश हो चुका है। साथ ही, मथुरा में केवल लड़कियों के लिए एक सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी गर्व जताया कि अब लड़कियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और भारतीय सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है और जल्द ही जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज का भारत वैसा ही है जैसा प्राचीन समय में विश्व गुरु हुआ करता था। उन्होंने छात्रों से कहा

कि वे स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि यदि वे खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों की मदद करने के बजाय खुद को मदद मांगनी पड़ेगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपनी सोच को सदैव सकारात्मक व ऊंची रखें। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष को सराहते हुए कहा कि वे जनजातीय समुदाय से आती हैं, लेकिन अपने कठिन परिश्रम के बल पर विधायक, मंत्री और राज्यपाल बनीं और अब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की सच्ची ताकत बताया। उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत में आज 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं और 55 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं। उन्होंने कहा कि भारत की इंटरनेट खपत अमेरिका और चीन को मिलाकर भी ज्यादा है। साथ ही, सड़कों का जाल तेजी से फैल रहा है और नई ट्रेनें शुरू की जा रही हैं।

विद्यालय के लिए की चार घोषणाएं विद्यालय में बनेगी आईसीटी लैब:
उपराष्ट्रपति ने विद्यालय की प्रगति को लेकर खुशी जताई और प्रिंसिपल की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय का सही दिशा में विकास हो रहा है और इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि तीन महीने में स्कूल में एक

आधुनिक कंप्यूटर लैब शुरू की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्कूल के लिए भेजेगे स्मार्ट बोर्ड: विद्यालय में शैक्षणिक संसाधनों में वृद्धि के लिए उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक स्मार्ट बोर्ड लगवाने की बात कही।

स्कूली बच्चों को दिल्ली आने का निमंत्रण
उपराष्ट्रपति ने स्कूल के बच्चों को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे समूहों में छात्रों को दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां उनके रहने-खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान वे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और वॉर मेमोरियल का दौरा कर सकेंगे।

स्कूल की लाइब्रेरी के लिए 1000 पुस्तक भिजवाएंगे
उपराष्ट्रपति ने स्कूली बच्चों को सिलेबस के अलावा भी किताबें पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के पुस्तकालय में उनके द्वारा 1000 पुस्तक भेजी जाएंगे जो आपकी रुचि की होंगी, जिनका निश्चित लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा।

ये रहे मौजूद
इस अवसर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, संभागीय आयुक्त पूनम, जयपुर रैजेंट आई जी अजय पाल लांबा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, विद्यालय की प्रधानाचार्य शारदा, सांगासी सरपंच अनीता ऐचरा सहित सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडीईओ उम्मेद सिंह महला ने किया।

खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों अभाव :

मरीजों को जाना पड़ रहा अलवर और जयपुर

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो
खैरथल! खैरथल तिजारा के जिला मुख्यालय पर सैटेलाइट हॉस्पिटल के सुविधाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सर्जन,स्त्री रोग,हड्डी रोग,नेत्र विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। वही अन्य रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी अभाव होने से रोगी परेशान हो रहे हैं। सुविधाएं बढ़े तो मर्ज दूर हो....

खैरथल सैटेलाइट अस्पताल में रोजाना करीब 500 से 650 मरीजों का आउट डोर होने पर भी गंभीर मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है. सरकार ने खैरथल मे अस्पताल को सेटेलाइट तो बना दिया,लेकिन सेटेलाइट जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है! अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ,चर्म रोग, नेत्ररोग,सर्जन,समेत अन्य विशेषज्ञ की सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आज भी गम्भीर स्थिति मे मरीजो को अलवर रेफर किया जाता है!

जागरूक नागरिक जीतेन्द्र कुमार प्रदनानी ने बताया जिला मुख्यालय होने के साथ रेलवे लाइन सहित अनेक सड़कों के होने के बावजूद यहां सर्जन नहीं है, ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है लेकिन सर्जन चिकित्सक नहीं होने की वजह से आप्रेशन थिएटर पर ताला लटका हुआ है , स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में डिलीवरी के दौरान आपातकालीन में अलवर भेजा जाता है , और सबसे जरूरी चर्म रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को मजबूरन बाहर से यहां आकर स्थानीय डाक्टरों से परामर्श लेनी पड़ रही है। वही कुछ लोग अलवर या जयपुर जाकर विशेषज्ञ डाक्टरों से इलाज करा रहे है!

खैरथल की सामाजिक संस्था खैरथल विकास मंच और अन्य संस्थाओ ने सरकार से खैरथल जिला मुख्यालय पर सेटेलाइट अस्पताल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कई बार की गई है !लेकिन चिकित्सको को नियुक्त नही किया जा रहा है !

खरीद केन्द्रों का नोडल प्रबंधक आरडी मीणा ने किया निरीक्षण

देईखेडा में गेहूं खरीद केंद्र की व्यवस्थाओं का अधिकारियों ने लिया जायजा

ब्यूरो –एनपीटी

बून्दी! !।कस्बे में एफसीआई गेहूं खरीद केंद्र का नोडल प्रबंधक आरडी मीणा ने मेला ग्राउंड में होने वाली गेहूं खरीद केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिये किसानों को अपनी फसल तुलाई के 48घंटे में भुगतान किया जाएगा परिस्वर की साफ सफाई छाया पानी बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित



करने को लेकर संवेदक को निर्देशित किया इस मौके पर मंडी सचिव सुरेश शर्मा,देईखेडा सरपंच राजकुमार मीणा प्रतिनिधि अशोक मीणा क्वालिटी इंस्पेक्टर राजकमल मीणा भुगतान अधिकारी राजवीर सिंह आदि मौजूद थे

रहमान खेड़ा जंगल में घूम रहे बाघ को वन विभाग ने किया ट्रैकुलाइज, कर चुका था 24 शिकार

लखनऊ। लखनऊ के रहमानखेड़ा में आतंक का पर्याय बने बाघ को पकड़ लिया गया है। बीते 90 दिनों में बाघ ने 24 शिकार किए। आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिल गई। रहमान खेड़ा जंगल में 90 दिनों से चहल कदमी कर रहे बाघ को वन विभाग की टीम ने बुधवार शाम सफलतापूर्वक ट्रैकुलाइज कर लिया है। यह बाघ आसपास के 60 गांवों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, अब तक यह 24 शिकार कर चुका था। वन विभाग की टीम ने विशेषज्ञों की मदद से बाघ को बेहोश करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। ट्रैकुलाइज करने के बाद उसे बीकेटी (बख्शी का तालाब) रेंज कार्यालय लाया जाएगा, जहां वन्यजीव चिकित्सकों की टीम उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। रहमान खेड़ा जंगल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस बाघ की उपस्थिति से लोग काफी दहशत में थे। कई बार ग्रामीणों ने बाघ को खुले में घूमते देखा था, जिससे खेती और पशुपालन पर भी असर पड़ रहा था। बाघ के हमलों के चलते ग्रामीणों को रात में बाहर निकलने में डर लगने लगा था। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से बाघ पर नजर रख रही थी। कैमरा ट्रैप, ड्रोन और स्थानीय ग्रामीणों की सूचनाओं के आधार पर उसका मूवमेंट ट्रैक किया गया। कई बार उसे सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच निकलता था। अंततः विशेषज्ञों की मदद से उसे ट्रैकुलाइज कर लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बाघ का पूरा मेडिकल चेकअप किया जाएगा। यदि वह स्वस्थ पाया जाता है, तो उसे किसी सुरक्षित जंगल या टाइगर रिजर्व में छोड़ा जा सकता है। यदि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो उसे पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा।

हिंदुस्तान स्काउट गाइड के नेत्र जांच व आपरेशन परामर्श शिविर

ब्यूरो –एनपीटी
बून्दी! समाज की नई पीढ़ी में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की भावना जगाती है स्काउटिंग – डॉ. माहेश्वरी
हिंदुस्तान स्काउट गाइड के नेत्र जाँच व ऑपरेशन परामर्श शिविर मे 170 रोगी लाभान्वित, 25 का होगा कैशलेस मोतियाबिंद ऑपरेशन
बूंदी। समाज की नई पीढ़ी में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की भावना जगाती है स्काउटिंग, ऐसा कहना हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वी. एन. माहेश्वरी का। डॉ. माहेश्वरी ने कहा कि स्काउट गाइड द्वारा नई पीढ़ी को बचपन से ही मिली अच्छे संस्कारों की शिक्षा से विद्यार्थियों का ही सर्वांगीण विकास नहीं होता बल्कि इससे राष्ट्र और समाज भी सुदृढ़ होता है।
बुधवार को हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय बूंदी द्वारा आयोजित निशुल्क नेत्र रोग जाँच व ऑपरेशन परामर्श शिविर का बाल बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वी. एन. माहेश्वरी, समाजसेवी के. सी. वर्मा



तथा समाजसेवी महावीर मनिहार के आतिथ्य और आईपी के जिला समन्वयक कृष्ण कांत राठौर की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया।
शिविर संयोजक व यूनिट लीडर आतिश वर्मा ने बताया कि शिविर में मुख्य नेत्र विशेषज्ञ व रिफ्रेक्टिव सर्जन डॉ संजय गुप्ता ने नेत्र जांच कर 170 रोगियों को परामर्श दिया और, 25 रोगी कैशलेस मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए।
इस मौके पर संबोधित करते हुए समाजसेवी के.सी. वर्मा तथा महावीर मनिहार ने स्काउट गाइड और

की इस अवसर पर डॉ.संजय गुप्ता ने अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सेवाकार्यों की जानकारी दी।
आईपा के जिला समन्वयक कृष्ण कांत राठौर ने कहा कि डॉ संजय गुप्ता ने कई शिविरों के माध्यम से मरीजों को लाभ दिया। उन्होंने कहा कि डॉ संजय गुप्ता सदैव निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद एवं मरीजों के सेवा में लगे रहते हैं। संस्था के प्रबंधक जय सिंह सोलंकी ने बताया कि इस शिविर मोतियाबिंद, कालापानी, नाखूना, नासूर, भंगापन, मूंदी पलकें,आँखों की एलर्जी, ड्राई आई , बच्चो में होने वाला मोतियाबिंद, बच्चो का नासूर, दृष्टिदोष चोट के पश्चात बनने वाला मोतियाबिंद मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप से होने वाली परदे की बीमारियों सहित नेत्र रोगों की जांच व उपचार प्रदान किया गया। इस अवसर पर यूनिट लीडर आतिश वर्मा, राकेश माहेश्वरी, संगीता प्रभु, ज्योत्सना कुमावत, मूल चंद शर्मा, साक्षी गोपाल, विनोद, मनोज मीणा, मोहित चौधरी, शिवराज चौधरी, शेर खान, सीताराम बैरवा, हर्ष हाडा मौजुद रहे।

किसान आईडी के शिविर 6 से 8 मार्च इन पंचायतों में आयोजित होंगे

शिविर में पंजीयन पर ही मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो
झुंझुनूं। जिले में फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान आईडी बनाने के शिविर तहसीलवार जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए हैं। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि 6 से 8 मार्च तक चिड़ावा तहसील की बुडानिया, गोवला, किठाना, खुडाना, श्योपुरा ग्राम पंचायत में, खेतड़ी तहसील की संजय नगर, दलेलपुरा, तातीजा,

नानूवाली बावड़ी, नंगली सलेदी सिंह, मेहाड़ा जादुवास ग्राम पंचायत में, गुढ़ागौड़जी तहसील की मानोता जाटान ग्राम पंचायत में, उदयपुरवाटी की सराय, झुंझुनूं की पातुसरी व आबूसर ग्राम पंचायत में, मलसीसर की बाजला, ककडेऊं कलां, हंसासरी, जाबासर, भूदा का बास, मंडावा तहसील की शेखसर, मोजास ग्राम पंचायत में, बुहाना तहसील की श्योपुरा, झारोडा, ढाणा, माईसदा, बुहाना ग्राम पंचायत में,

वन कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के आश्वासन पर किया धरना समाप्त



के द्वारा जब्त कर राजतहवील में लेकर वहां से रवाना हुए। तभी बीच रास्ते में अवैध खनन कताओं द्वारा स्टाफ के साथ कुल?हाड़ी व सरीयों से जानलेवा हमला शुरू कर दिया। जिससे कर्मचारियों को गम्भीर चोट आई और घायल हो गये। राजकीय वाहन को स्टाफ जान बचाकर भागे इस बाबत जिला रू?तर पर आज बूंदी जिले में जिला कलेक्टर बूंदी अक्षय गोदारा को ज्ञापन सोपा।

ज्ञापन से पूर्व वन भवन जिला बूंदी से समस्त अधिकारी /कर्मचारी जंगी प्रदर्शन करते हुए ,नारे लगाते हुए जिनमें मुख्य रूप से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के संरक्षक पुरुषोत्तम पारीक, संयुक्त महासंघ जिला अध्यक्ष सत्यवान शर्मा,रेंजर नरेंद्र सिंह सोलंकी (अध्यक्ष, वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ,बूंदी, दसरथ सिंह (क्षे. व.अ. केपाटन)शिव प्रकाश चौधरी (क्षे.व.अ. हिण्डोली) मनीष कुमार शर्मा ,कविवता जाटा)रीना रावल,निशा मीणा,ज?योति मीणा राराय

मुख्य मांगे यह रही

(1) वन कर्मचारी फिल्ड में अपना दायित्व निर्वाह करते हुए तथा राजहित में ड्यूटी करते हुए वन अपराधियों व भूमाफियों द्वारा जंगल सुरक्षा करते हुए उस वक्त कही बार ऐसी अप्रिय घटना जान से मारने की धमकी होती है। ऐसे में कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। अपराधीयों के खिलाफ आई.पी.सी. की गम्भीर धाराओं व राज० वन अधिनियम के तहत शक्त कार्यवाही अमल लाई जाये।
2 ऐसे कर्मचारीयों को आधुनिक हथियार मुहैयाया किया जाये और सभी रेंज व नाका स्तर पर वाहन उपलब्ध करवाया जाये। जंगल में आपाल काल में जल्दी से पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जाये। सभी कर्मचारियों को जङ्ग सा की अनुशंषा पर शस्त्र लाइसेन्स जारी हो साथ ही फिल्ड स्टाफ के साथ ऐसी अप्रिय घटना होने पर उच्च अधिकारीयों द्वारा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

सीएम हेमन्त सोरेन ने नवचयनित 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति

एनपीटी ब्यूरो
रांची, झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में नवचयनित 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष भी सितंबर माह में 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। गुरुवार को एक बार फिर से 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा आपकी जिम्मेवारी होगी युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दे, ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिले। सरकार के जिम्मेवार कर्मी के रूप में योगदान दे। आने वाली पीढ़ी को ऐसा निखारे



कि उनके पीछे रोजगार चले। विभिन्न सेवाओं में नौकरी देनी है। आज श्रम विभाग में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में कोशिश है युवाओं को रोजगार और नौकरियों में आवश्यकता अनुसार

शामिल करने की। लोग तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। तकनीकी रूप से सभी को दक्ष होना होगा। श्रम विभाग द्वारा कई कोर्स शामिल किये गये हैं। कहा एआई का कोर्स भी शामिल करे।

आउटरीच कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों को किया गया जागरूक



एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झा०खंड), झालसा रांची के निदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में नब्बे दिवसीय आउटरीच सह- विधिक

जागरूकता कार्यक्रम विद्यालय समेत पाकुड़ के सभी प्रखण्डों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पीएलवी अमूल्य रत्न, रविदास, एजारूल शेख, विजय राजवंशी ने प्राथमिक विद्यालय महुआडांगा में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बाल विवाह, बाल श्रम पर विशेष रूप से जागरूक किया। वही पीएलवी

चन्दन रविदास ने महेशपुर प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को डायन प्रथा, साइबर ठग से बचाव, डिजिटल अरेस्ट समेत नालसा के योजनाओं पर जागरूक की। साथ ही जागरूक पर्ची वितरण किया गया। वही अन्य प्रखण्डों में सम्बन्धित पैरा लीगल वॉलंटियर्स के टीम ने आउटरीच कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता पर विस्तृत जानकारी दी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने हेतु योग्य व्यक्ति को आवेदन सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

जिले के पांच मुखिया आईआईएम बौद्धगया में लेंगे प्रशिक्षण



एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झा०खंड), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत आईआईएम, बौद्धगया में आयोजित होने वाले पांच दिवसीय प्रशिक्षण (08 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025) में पाकुड़ जिले से 09 मुखिया प्रशिक्षण में भाग लेंगे। जिसमें अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के बोहरा पंचायत की मुखिया क्रांति कुमारी, हिरणपुर प्रखण्ड के तोड़ाई पंचायत की मुखिया तेरेसा टुडू, लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड

के तालपहाड़ी पंचायत की मुखिया मीनू हांसदा, महेशपुर प्रखण्ड के शहरग्राम पंचायत की मुखिया सुजाता हेम्ब्रम, पोखरिया पंचायत की मुखिया सुरुधनी मुर्मू, पाकुड़ प्रखण्ड के दादपुर पंचायत की मुखिया बड़की हेम्ब्रम, मालपहाड़ी पंचायत की मुखिया सविता हेम्ब्रम एवं पाकुड़िया प्रखण्ड के बन्नोग्राम पंचायत की मुखिया अनीता हेम्ब्रम एवं तेतुलिया पंचायत की मुखिया मोनिका हेम्ब्रम प्रशिक्षण में भाग लेंगी।

महिलाओं के खाते में जल्द हस्तांतरित की जा सकती है मईया सम्मान योजना की राशि, कवायद तेज

एनपीटी ब्यूरो
झारखण्ड में मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना इस बार कई महिलाओं का झटका देने वाला है। अगले दो से तीन दिन के भीतर जो मईया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में पहुंचने की सम्भावना जताई जा रही है, उस लिस्ट से कई महिलाओं के नाम गायब होंगे। जानकारी मिल रही है कि करीब एक लाख महिलाओं को इस बार से 2500 रुपये की राशि नहीं दी जायेगी। आधार सीड डेटा में 37,55,233 लाभुकों के नाम दर्ज हैं। शेष 5,52,855 लाभुकों के खाते में आधार सीडिंग के बाद पैसे भेजे जायेंगे। इस योजना के लाभुकों की संख्या के हिसाब से टॉप 5 जिलों की बात करे तो सबसे ज्यादा रांची में 365512, गिरिडीह में 354511, धनबाद में 309879, पलामू में 284006 और बोकारो में 279746 लाभुक हैं। वही 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में राशि जायेगी या नहीं? इस पर विभाग की कमेटी फैसला लेगी। ऐसे में उम्मीद यही है कि 52 लाख लाभार्थी महिलाओं में से इस बार सिर्फ 37-38 लाख महिलाओं के खाते में ही पैसे भेजे जायेंगे। करीब 12 लाख महिलाओं का योजना से इस बार पत्ता कट सकता है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक महिला दिवस के दिन या पूर्व संंध्या पर 8-9 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आ सकते हैं। इस बार उन्हें तीन महीने के 7500 रुपए एकमुश्त मिलेंगे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम रोक दिया गया है। अपात्र लाभुकों की पहचान की जा रही थी। अब स्कूटनी के बाद अब तक 43,08,088 पात्र लाभुक मिले हैं, लेकिन 13,53,703 लाभुकों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है।



जनहित का बजट पेश किए जाने पर सीएम व वित्तमंत्री बधाई के पात्र हैं- विजय शंकर नायक

एनपीटी ब्यूरो
रांची (झा०खंड), आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश करने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राज्य में सिर्फ बजट का आकार बढ़ाना राज्य के विकास का पैमाना नहीं बल्कि सम्पूर्ण बजट की राशि शत- प्रतिशत योजना मद में खर्च करना ही विकास का पैमाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट की राशि का आकार बढ़ाना अच्छी बात है, मगर बजट की राशि शत-प्रतिशत खास कर योजनामद की राशि खर्च नहीं होना राज्य के लिए शुभ नहीं है। इसलिए सरकार इसपर विशेष फोकस करे और शत- प्रतिशत बजटीय राशि खर्च हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करे। नायक ने आगे कहा कि राज्य सरकार के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर

के द्वारा वार्षिक बजट 1,45,400 करोड़ रु पेश करने का स्वागत किया है। यह बजट राज्यहित में ऐतिहासिक क्रान्ति लायेगी जब सम्पूर्ण योजनामद की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री ने विकास दर में बढ़ावा हो, इसके लिए सभी विभागों को प्राथमिकता दिया है। सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ मईया सम्मान योजना, ग्रामीण विकास, खेलकूद में काफी फोकस किया गया है जो निश्चित रूप से भविष्य मे यह बजट लोगों के लिए जनकल्याणकरी साबित होगा और भविष्य में राज्य का विकास दर तेजी से बढ़ेगी। कहा ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन विजय और वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा जनहित का बजट पेश किए जाने पर दोनो बधाई के पात्र हैं।

विद्यालय की अव्यवस्था देख भड़के डीसी, जमकर लगाई फटकार, कारवाई का दिया निर्देश

एनपीटी ब्यूरो
लातेहार (झा०खंड), लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष कुमार गुप्ता ने बुधवार को बालूमाथ प्रखण्ड पहुंचकर सरकार द्वारा संचालित कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उच्च विद्यालय सेरेगड़ा पहुंचे जहां शिक्षक क्लास रूम के जगह इकट्ठा होकर आपस में गपशप करते नजर आए। वही नियमानुसार मध्यान भोजन में खामी, विद्यालय में गंदगी का अंबार ,पानी की कमी देखकर उपायुक्त भड़क गए एवं सभी शिक्षकों को एक कमरे में बुलाकर जमकर फटकार लगाई। वही मौके पर उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू, को कार्रवाई का निर्देश दिया। उपयुक्त ने सेरेगड़ा में

कई लोगों की समस्या सुनी। इसके बाद उपायुक्त ने सेरेगड़ा आंगनबाड़ी , उपस्वास्थ्य केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकान पहुंचकर निरीक्षण किया। उपयुक्त बालूमाथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे जहां बच्चों से हर समस्या से रूबरू हुए। 12वी की छात्राओं से पूछा कि यहां से निकलने के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं। इस पर कई बच्चियों ने बताया कि कोई एमबीबीएस ,बी फार्मा ,जीएनएम, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की बात कही। वही बच्चियों ने कहा कि हम लोग 7 वर्षों से कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहां से निकलने के बाद हम लोग अपने-अपने घर में जाएंगे तो हम लोग घर मे रहकर अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकते



हैं। इसलिए हम लोगों को जिला प्रशासन कोई व्यवस्था कराकर पढ़ाई को सुचारू रखवाने में सहयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि आपकी बात को गंभीरता से लेकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं छात्र पूजा कुमारी एवम नैन्सी कुमारी ने कहा कि एक गोष्ठी का आयोजन कर हम लोगों के अविभावक को जागरूक करने का कार्य किया जाए ताकि यहां से निकलने के बाद हम लोगों

पाकुड़ के जीवाश्म भंडारण क्षेत्र में स्थापित होंगे जियोपार्क

एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़ (झा०खंड), 4 मार्च 2025 को भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार के भू- विरासत एवं भू-पर्यटन संवर्धन केन्द्र हेतु डॉ रणजीत कुमार सिंह, भू वैज्ञानिक सह-पर्यावरणविद मॉडल कॉलेज राजमहल साहिबगंज के प्राचार्य झारखंड के पाकुड़ जिले में बरमसिया, सोलगाडिया, सोनाजोड़ी अन्य पहाड़ समेत आसपास के महत्वपूर्ण संरक्षित जीवाश्म स्थलों का दौरा किया। इस क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत करने और उन्हें अपने आसपास के क्षेत्र में मौजूद लकड़ी के जीवाश्मों के संरक्षण और परिरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कई दशकों से स्थानीय ग्रामीण यह सोचकर जीवाश्म लकड़ी की पूजा करते हैं कि यह आसपास के चट्टानों से अलग है, लेकिन अब पिछली एक सदी में भारत के भूविज्ञानी विशेष रूप से डॉ रणजीत कुमार सिंह, जीएसआई, बीएसआईपी देश के नामचीन विश्वविद्याल कॉलेज शैक्षणिक संस्थान और दुनिया भर के गोंडवाना



पौधे जीवाश्म शोधकताओं ने गोंडवाना वनस्पतियों और जीवाश्म लकड़ी की व्यवस्थित रूप से पहचान की और उन्हें वर्गीकृत नहीं, झारखण्ड की इन अनूठी जीवाश्म लकड़ी को अगली पीढ़ी, भूविज्ञानी शोधकताओं और इस क्षेत्र के विज्ञान और वैज्ञानिक समझ में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए संरक्षित और संरक्षित करने की सख्त जरूरत है। इसे देखते हुए, वन्य विभाग पाकुड़, जीएसआई डॉ रणजीत कुमार सिंह ने आम लोगों, राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयास से अनूठी जीवाश्म लकड़ी के संरक्षण के संबंध में झारखण्ड वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी चन्द्रा के साथ भू- विरासत विकास योजना का

प्रस्ताव रखा। जीएसआई ने स्थानीय ग्रामीणों, प्रशासकों, वन विभाग, झारखण्ड राज्य के इकोटूरिज्म के साथ बातचीत की और इस क्षेत्र में एक अलग जियोपार्क कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। क्षेत्र में जीवाश्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए भू-स्थलों के व्यवस्थित विकास के लिए अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया। ऐसे जीवाश्म वनों का विरासत मूल्य अद्वितीय है और उन्हें उनकी प्राकृतिक स्थितियों में संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसलिए यूनेस्को द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकृत मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े भू-पार्क का प्रस्ताव किया जायेगा।

शिवरात्रि मेले के समापन पर हास्य प्रोग्राम का उपासना मरांडी ने किया उदघाटन



एनपीटी ब्यूरो
पाकुड़िया प्रखण्ड के मोंगलाबांध स्थित बैद्यनाथ मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित शिवरात्रि महोत्सव के अन्तिम दिन मंगलवार देर रात्रि को पुरलिया के मशहूर बांग्ला हास्य कलाकार काला चांद फांका चांद नाइट प्रोग्राम आयोजित हुई। वही कार्यक्रम के बतौर मुख्यातिथि महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाये विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी के सुपुत्र सह- क्षेत्र के उभरता हुआ युवा नेत्री उपासना मरांडी उर्फ पिंकी ने प्रोग्राम का उद्घाटन फीता काट कर किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दीपक साहा संचालक कार्तिक पाल सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने

फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्यातिथि युवा नेत्री उपासना मरांडी उर्फ पिंकी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मोंगला बांध में प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर इतनी बड़ी कार्यक्रम की जाती है, इसके लिए कमेटी के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने सभी दर्शकों एवं ग्रामीणों का इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर शोभा बढ़ाने को लेकर भी बधाई दिया। मौके पर बिस्वजीत दास, मुकेश यादव, सूरज रविदास, कैलास साहू, आलोक भगत सहित ज्ञामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता, कमेटी के सदस्य, ग्रामीण एवं हजारों की संख्या में दर्शकों उपस्थित थे।

अवैध देशी शराब पर प्रशासन की कारवाई
एनपीटी ब्यूरो
बीते मंगलवार देर रात को उत्पाद विभाग के द्वारा पाकुड़ प्रखण्ड अन्तर्गत गुलदाहा ग्राम में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के क्रम में 7 लीटर अवैध चुलाई शराब एवं 110 किलोग्राम अवैध जल मिश्रित जावा महुआ बरामद किया गया। जल मिश्रित जावा महुआ को घटना स्थल पर विनष्ट किया गया एवं अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया।

की मांग की। उपायुक्त ने वार्डन शिखा कुमारी से पूछा कि आपके पास स्मार्ट क्लास के लिए अतिरिक्त कमरा है या नहीं। उपायुक्त में अतिरिक्त कमरा बनवाकर स्मार्ट कलश चलाने का निर्देश दिया। इससे पहले उपायुक्त कस्तूरबा विद्यालय में पहुंचते ही वहां की बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर एवम बुके देकर उपायुक्त एवं पदाधिकारी स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने देखा कि कस्तूरबा की कई बच्चियों उपायुक्त को अपने हाथों से चित्र बनाकर दीवारों में लगा रखा था। वहीं कुछ बच्चियों ने उपायुक्त से अपने जीवनी के विषय में पूछ डाला। इस पर उपायुक्त ने सहजता से कहा कि मैं कंप्यूटर से इंजीनियरिंग किया था 2 साल

तक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया और मैं क्वालीफाई हो गया। मैं एक आपलोगो जैसा ही साधारण परिवार से आता हूं और हमारे पिता सरकारी नौकरी करते थे। इस मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम साहू, पंचायती राज पदाधिकारी श्रेयांश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा, जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कमलेश कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश महतो ,लातेहार एसडीएम अजय कुमार ,जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बालूमाथ बीडीओ सोमा उराव समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

एमआईटी सीएसई विभाग ने एचसीएल टेक कैंपस में किया सफल औद्योगिक दौरा

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मेरठ। एमआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) विभाग ने 5 मार्च 2025 को एचसीएल टेक कैंपस में एक सफल औद्योगिक दौरे का आयोजन किया। इस दौरे में विभाग के 50 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटना था। दौरे के दौरान, एचसीएल गुवी फैमिली की ओर से एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व श्री कौशल देव कश्यप ने किया। सत्र में वर्तमान बाजार प्रवृत्तियों, कुशल इंजीनियरों की बढ़ती मांग और आर्टिफिशियल



इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग में हो रहे नवीनतम विकास पर चर्चा की गई। उन्होंने छात्रों को कैस्प्टोन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को समझाया, जिससे वे आईटी सेक्टर में सफल करियर बना सकें। छात्रों को आईटी इंडस्ट्री के संचालन, सर्विस-बेस्ड कंपनियों के कार्यप्रणाली और तकनीकी क्षेत्र में

उपलब्ध करियर के अवसरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस औद्योगिक दौरे की सफलता का श्रेय सीएसई विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) विकास श्रीवास्तव एवं अन्य प्राध्यापकों को जाता है, साथ ही इकोज एमआईटी टीम के समर्पित प्रयासों ने इसे और प्रभावी बनाया। यह औद्योगिक दौरा छात्रों के लिए एक

महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव साबित हुआ, जिससे वे आईटी उद्योग के व्यावहारिक पहलुओं और नवीनतम तकनीकों को बेहतर ढंग से समझ सकें। एमआईटी का सीएसई विभाग छात्रों को कॉर्पोरेट जगत और उभरती तकनीकों की गहरी समझ प्रदान करने के लिए लगातार ऐसे अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौर सिटी सिकंदर पुर भोपुरा के गंदे नाले के पानी की निकासी वार्ड 37 शालीमार में विरोध

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

साहिबाबाद। गौर सिटी सिकंदर पुर की सोसाइटी के बिल्डर द्वारा अपने प्रोजेक्ट की गंदे पानी की निकासी के नाले को वजीराबाद रोड को काट कर वार्ड 37 शालीमार गार्डन में जोड़ा जाना है। जिसका स्थानीय पार्श्व रवि भाटी ने विरोध किया है। उनका कहना है पहले ही क्षेत्रीय नाला ओवर फ्लो रहता है। इस



नाले के जुड़ने से पूरा क्षेत्र गंदे पानी ओर गंदगी से भर जाएगा। विक्रम एनक्लेव, 80 फूट, छाबड़ा कॉलोनी, शालीमार, के करीब 50 हजार लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इस नाले को न जोड़ा जाए।

शिक्षकों की संयुक्त कार्रवाई समिति (टीजेएसी) राजवार ने नवनियुक्त क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी श्री शबीर अहमद बदाना से मुलाकात की

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

5 फरवरी 2025 जचलदारा राजवार- शिक्षकों की संयुक्त कार्रवाई समिति (टीजेएसी) राजवार के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सज्जाद अहमद खान के नेतृत्व में कार्यकारी सदस्यों के साथ नवनियुक्त क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (जेडईओ) श्री शबीर अहमद बदाना से मुलाकात की।

टीजेएसी टीम ने श्री बदाना को जेडईओ राजवार के रूप में उनके नए कार्यभार के लिए बधाई दी और प्यार के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किए और उसके बाद जोन में शिक्षकों और छात्रों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उठाई गई प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:

- क्षतिग्रस्त स्कूल भवन
 - जरूरतमंद स्कूलों को स्टाफ उपलब्ध कराना
 - शीतकालीन असाइनमेंट के लिए नियोजित शिक्षकों के पक्ष में टीए
 - अन्य प्रासंगिक मुद्दे
- जेडईओ ने टीजेएसी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इन मुद्दों को निर्धारित समय सीमा के भीतर, अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अधिकार क्षेत्र में हल करेंगे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों



पक्षों ने राजवार में शिक्षा की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख कार्यकारी सदस्य शामिल थे जिनमें मीर इकबाल जिला आयोजक, बिलाल अहमद पीरजादा, बिलाल अहमद डार, मुदासिर अहमद खान, तजामुल इस्लाम, जहांगीर अहमद वार, वकील अहमद भट, गौर नबी मीर, मुश्ताक अहमद राशि, मुश्ताक अहमद राशि, इश्फाक राशिद, मुश्ताक अहमद मीर, सैयद एजाज, नजीर अहमद बजाद, तवान अली, मोहम्मद शफी और अन्य शामिल थे।

जिला महिला अस्पताल में आयुष्मान वार्ड किया बंद

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। जिला महिला अस्पताल में संचालित आयुष्मान वार्ड शुरू होने के बाद एक साल में ही बंद कर दिया गया। अब आयुष्मान कार्ड धारक महिलाओं का भी इलाज और प्रसव सामान्य वार्ड में ही होगा। दस बेड के वार्ड में रोजाना पांच से छह महिलाएं भर्ती होती थीं। अस्पताल की तीन स्टाफ नर्स को डूढ़ाहेड़ा संयुक्त अस्पताल में भेजने के बाद कर्मियों की कमी हो गई है। अस्पताल में तीसरी मंजिल पर पांच कमरों में 10 बेड बनाए गए हैं। कमरों के बाहर तीमारदारों के लिए आयुष्मान लॉन्ज की

व्यवस्था भी की गई है। 16 मार्च को आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था।

आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाली महिलाओं को निजी अस्पताल जैसी सुविधा मिल रही थी। वहां पर तीमारदारों को टीबी देखने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। आयुष्मान योजना में अस्पताल को प्रति प्रसव के 12,900 से 16 हजार रुपये तक का भुगतान मिल रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 20 से 25 प्रसव होते हैं। इनमें पांच से छह महिलाओं का प्रसव आयुष्मान योजना में किया जा रहा है।

अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से 250 से अधिक प्रसव कराए जा चुके हैं। पहले सभी मरीजों को सामान्य वार्ड में भर्ती किया जा रहा था, प्राइवेट वार्ड को आयुष्मान वार्ड में बदलकर कार्ड धारक महिलाओं को भर्ती किया जा रहा था। अस्पताल की सीएमएस डॉ अल्का शर्मा ने बताया कि अस्पताल में दस स्टाफ नर्स की कमी पहले से ही थी। अब तीन स्टाफ नर्स को डूढ़ाहेड़ा भेज दिया गया है। स्टाफ की कमी के कारण वार्ड बंद किया गया है। मरीजों का इलाज और भर्ती किया जाएगा, लेकिन आयुष्मान वार्ड स्टाफ वापस आने तक बंद रहेगा।

बार एसोसिएशन के सचिव पद पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश, उपजिलाधिकारी ने किया निरस्त

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद। सचिव पद का चुनाव निरस्त करते हुए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अरुण दीक्षित ने दो सप्ताह में दोबारा कराने का आदेश दिया है। आदेश में एसडीएम ने कहा है कि विवेचना के आधार पर बार एसोसिएशन के चुनाव वर्ष 2024-25 में सचिव पद का निर्वाचन निरस्त किया जाता है। बार की एल्डर्स कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह बार एसोसिएशन गाजियाबाद में सचिव पद के निर्वाचन मॉडल बार्सलॉज में उल्लिखित उपनियमों के अनुसार मतदाता सूची का पुननिरीक्षण कर चुनाव कार्यक्रम घोषित करते

हुए दो सप्ताह के अंदर चुनाव सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। सचिव पद के प्रत्याशी हरेंद्र कुमार गौतम ने आरोप लगाया था कि बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 19 जुलाई 2024 में फर्जी मतदाता सफ्लीमेंट्री सूची बनाकर बिना एल्डर कमेटी के चुनाव संपन्न कराया गया। हरेंद्र का आरोप था कि सचिव पद पर मतगणना के दौरान विजयी होने के बाद भी बार-बार मतगणना करके बेईमानी पूर्वक सचिव पद पर कार्य करने नहीं दिया गया। हारे हुए प्रत्याशी अमित नेहरा को विधि विरुद्ध जाकर षड्यंत्र के तहत सचिव घोषित किया गया।

अधिवक्ता को कॉल पर मिली धमकी

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

लोनी। खन्नानगर कॉलोनी में रहने वाले अधिवक्ता जाहिद ताज अली को फोन पर धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दुबई में बैठे कंपनी के संचालक की शिकायत करने पर धमकी देने का आरोप है। पीड़ित ने बताया कि उनके

फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि तुम्हारी हत्या की सुपारी ले ली गई है। इसलिए बचकर रहना। तुमने लविश भाई की कंपनी के खिलाफ शिकायत की है।

एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि फोन नंबर की डिटेल् खंगाली जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उनकी संस्था आम लोगों



की मदद करती है। कुछ दिनों पहले फर्जी कंपनी के खिलाफ सीबीआई साइबर सेल व गृह मंत्री अमित शाह को लिखित शिकायत की थी। कंपनी का संचालन दुबई में बैठा नवाब

उर्फ लविश चौधरी कर रहा है। भारत में अपने एजेंटों द्वारा लोगों को ट्रेडिंग के नाम से निवेश कराता है। इस कंपनी की सभी मीटिंग और कार्यक्रम दुबई व थाईलैंड में किए जाते

हैं। जिसमें लोनी समेत आसपास के लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस कंपनी में लेनदेन गैर कानूनी रूप से किया जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि करीब 90 लाख रुपये लोनी और आसपास के लोगों से निवेश कराया गया है। कुछ पीड़ित उनके पास आए और मदद मांगी तो उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से शिकायत की थी।

लालगढ़ में जलग्रहण विभाग की वाटरशेड यात्रा ने दिया वर्षा जल संरक्षण का संदेश

नेशनल प्रेंस टाईम्स ब्यूरो

प्रतापगढ़,अरनोद। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जलग्रहण विकास घटक के तहत वाटरशेड यात्रा दिनांक 05.03.2025 को ग्राम पंचायत लालगढ़ पहुँची यात्रा के ब्लॉक नोडल अधिकारी राजेन्द्र धाकड़ अधीशापी अभियंता ने परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 8 ग्राम पंचायतों के 26 गाँव, कुल क्षेत्रफल 3446.39 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अन्तर्गत उपचारित किया जा रहा है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधि अन्तर्गत अमृत सरोवर, एनीकट, पक्का चैक डैम, मिनी परकुलेशन टैंक, सीसीटी, सॅकन पोण्ड, खेतों में मेडबंदी कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मय रिचार्ज शॉफ्ट के कुल 20 कार्य, लागत 120.30 लाख रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 37 कार्य, लागत 66.75 लाख रुपए कार्य मानसून से पूर्व पूर्ण करवाये जाएंगे उत्पादन गतिविधि अन्तर्गत 64 केटलशेड कार्य लागत 25.37 लाख रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके है जीविकोपार्जन मद अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को शुरूआती मजबूती हेतु रिवोल्विंग फंड से 163



समूहों को 57.50 लाख एवं सामुदायिक निवेश निधि में व्यापार हेतु 80 समूहों को 51.16 लाख रुपए दिये गये है। यात्रा के जिला नोडल अधिकारी मनोज कुमार अधीक्षण अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्षा जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, जल संरक्षण के महत्व को समझाना साथ ही विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। यात्रा की अध्यक्षता सरपंच उदयलाल मीणा ग्राम पंचायत

लालगढ़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मण्डल अध्यक्ष बालुराम डांगी पं. स. अरनोद रहे, जिन्होंने जलग्रहण विभाग के कार्यों की सराहना की साथ ही वर्षा जल संरक्षण के प्रति स्थानीय लोगों को जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया तथा बताया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जलग्रहण विकास घटक से कराये जाने वाले कार्यों से भू-जल स्तर में बढ़ोतरी होगी जिससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी की

उपलब्धता बढ़ेगी व किसानों की आय में इजाफा होगा। इनके द्वारा वर्षा जल संरक्षण की आमजन को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में सम्मत लाल खटीक विकास अधिकारी पं, स. अरनोद पंचायत समिति सदस्य शिवनारायण डांगी व खेमराज मीणा मण्डल महामंत्री केशुराम जी मीणा व संजय शाह महामंत्री मंत्री गणपत धनगर उप जिला मंत्री रवि शर्मा अमृत मीणा ओम प्रकाश प्रजापत मण्डल मंत्री गोपाल मीणा प्रेमलाल मीणा मनीष कोठारी फतेहगढ़ सरपंच नेरूलाल मीणा साखथली खुर्द सरपंच रामलाल मीणा सहायक अभियंता जयेश सोमिया स्थानीय गामवासी उपस्थित रहें राजीविका स्वयं सहायता समूह नारसिंग माता की महिलाओं व स्थानीय महिलाओं द्वारा कलश यात्रा में भाग लिया गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ के प्रधानाचार्य मय स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा प्रभात फेरी रंगोली इत्यादि गतिविधियों द्वारा ग्रामवासियों को वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया श्रमदान का कार्यक्रम लालगढ़ तालाब एवं पौधारोपण का कार्यक्रम ग्रामपंचायत लालगढ़ परिसर में किया गया।